सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

भोपाल

गुरुवार, 04 जून, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 272, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

कमजोर रहा मानसून तो महंगाई का तड़का लगना तय

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

मौसम विभाग द्वारा 29 मई को जून से सितंबर मानसून के दौरान 10 प्रतिशत कम बरसात का पूर्वानुमान बेहद चिंता का कारण बन गया है। इससे पहले जारी पूर्वानुमान में 8 प्रतिशत कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई थी। लगभग दस साल बाद देश में कमजोर मानसून के हालात रहने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के लिए यह इसलिए और भी अधिक चिंतनीय हो जाता है कि एक और अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर के आसार नहीं दिख रहे हैं और इसके कारण भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश कच्चे तेल और गैस की समस्या से दो चार हो रहे हैं और इसका सीधा असर महंगाई बढ़ना हो रहा है। दूसरी और अब अल नीनो प्रभाव से इस साल कमजोर मानसून के कारण 10 प्रतिशत कम बरसात होने से हालात और भी गंभीर होने की संभावना बनती जा रही है। करीब दस साल बाद ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तर पूर्व को छोड़कर समूचे देश में कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता है कि पिछले सालों में भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान लगभग सटीक रहने लगे हैं। मजे की बात यह है कि इस साल गर्मी भी भीषण पड़ रही है और पिछले एक माह में ही जलाशयों में उपलब्ध पानी में तेजी से कमी आई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश के प्रमुख 166 जलाशयों में कुल भराव क्षमता का 24 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है और तेजी से पानी कम होता जा रहा है। दक्षिण भारत के हालात अधिक गंभीर है और वहां लगभग 17 प्रतिशत ही पानी रह गया है। उत्तरी भारत के जलाशयों में 26 तो पश्चिमी भारत के जलाशयों में 28 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है। मानसून भी तय समय से बिलंबित हो रहा है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था मानसूनी बरसात पर बहुत कुछ निर्भर करती है। देश में मानसून सीजन में 87 सेमी बरसात होती है। पूर्वानुमानों को माने तो 2018 में 91 प्रतिशत बरसात हुई थी उसके बाद के सालों में मानसून लगभग अच्छा ही रहा है। पिछले सालों में मानसून की स्थिति देखें तो 2023 में मानसून अवश्य कमजोर रहा है अन्यथा देश में मानसूनी वर्षा 100 प्रतिशत के आसापास व इससे अधिक ही रही है। कमजोर मानसून के कारण भूजल स्तर में गिरावट, अधिक पानी पर निर्भर धान, तिलहन और दलहन की फसल प्रभावित होगी और इस कारण से खाद्य महंगाई बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इससे आम आदमी की थाली पर असर पड़ेगा और सब्जी, दाल और अनाज सभी के भाव बढ़ने का असर दिखाई देगा। इसी तरह से देश के अनेक हिस्सों में पीने के पानी की दिक्कत आम है। बांधों में तेजी से पानी की कमी और मानसून कमजोर रहने से पानी की कम आवक रहती है तो निश्चित रुप से सिंचाई व पेयजल दोनों के लिए पानी की दिक्कत होगी। जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन पर असर होगा तो कुल मिलाकर अर्थ व्यवस्था को प्रभावित होने से कोई नहीं रोक सकता।

दरअसल देश में एक समय था जब सूखा आम होता था और व्यापक स्तर पर अकाल राहत कार्य संचालित होते थे। हांलाकि देश के हालातों में काफी सुधार हुआ है और अकाल को तो लगभग भूल ही चुके हैं। पर सवाल वहीं का वहीं है कि जल संचयन के जो प्रयास होने चाहिए थे और उनका जिस तरह का प्रभाव पड़ना चाहिए था वह अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार के सामने कमजोर मानसून के हालात से निपटने की बड़ी चुनौती आने वाली है। सबसे अधिक तो जल संग्रहण की चुनौती होगी क्योंकि प्राकृतिक जल संग्रहण के रास्ते शहरीकरण की भेंट चढ़ चुके हैं। दीर्घकालीन सोच के साथ ठोस प्रयास नहीं होने से बरसात के पानी का सही तरीके से संग्रहण भी नहीं हो पा रहा है। जितने पानी की साल भर आवश्यकता होती है उससे अधिक बरसाती पानी तो बह जाता है। इसके अलावा पानी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही बढ़ गए हैं। कम पानी से तैयार होने वाली फसलों की किस्में विकसित करने में हम अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पायें हैं। पांच नदियों के प्रदेश पंजाब तक में पानी का संकट होने लगा है। खेती ही नहीं घरेलू जरुरतों में भी पानी का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। टायलेट और कूलरों में पानी की खपत बहुत अधिक बढ़ गई है। जल बचाओ मात्र स्लोगन ही रह गया है और इसका असर दिखाई नहीं देता। इसी तरह से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार तो बहुत किये गये हैं पर उनके निर्माण में जिस तरह की लापरवाही बरती गई है वह किसी से छिपी नहीं हैं। क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कितना सफल रहा है वह सामने हैं। बाहरमासी नदी नालें तो अब कल्पना की बात हो गए हैं बल्कि बरसाती नदियां भी बरसात में एकाध बार ही पूरे वेग से बहती दिखती है। ऐसे में गंभीरता को तो समझा ही जा सकता है।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि मानसून हमेशा सामान्य ही रहेगा यह सोचना अपने आप में गलत होगा। जिस तरह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जंगल घटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं वह किसी और की देन नहीं हमारे कारण ही हो रहा है। हालात यह हो गए हैं कि सर्दी में सर्दी नहीं और गर्मी में गर्मी को तरसने लगे हैं। यहां तक कि इस बार तो बसंत की प्रतीक्षा ही करते रह गए हैं। जनवरी फरवरी में सर्दी तो फिर मार्च अप्रेल में गर्मी का असर देखा गया। बसंत कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। कहने का अर्थ है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम सामने हैं। प्राकृतिक विपदाएं अधिक होने लगी है। ग्लेसियरों में तेजी से बर्फ पिघल रही है, समयपर बर्फवारी कम होने लगी है। बेमौसम आंधी ओलावृष्टि आम होती जा रही है। खैर यह विषयांतर होगा पर कहीं ना कहीं मानसून को लेकर दीर्घकालीन रणनीति बनानी ही होगी ताकि कमजोर मानसून का जनजीवन और अर्थ व्यवस्था पर व्यापक असर नहीं पड़े। सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

इलेक्ट्रिक कार से चलेंगे सीएम मोहन

रेंज 500 किमी, नंबर- वीबी 2047 मिला

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक कार (ईवी) से सफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने का फैसला किया है।

इसका मतलब विकसित भारत बताया, आज काफिले में शामिल होगी

इसके लिए महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार एक्सईवी 9ई खरीदी गई है। यह बुधवार से मुख्यमंत्री के काफिले का हिस्सा बनेगी। मुख्यमंत्री बुधवार शाम दिल्ली रवाना होते समय मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक इसी कार से जाएंगे। मुख्यमंत्री की नई इलेक्ट्रिक कार का नंबर एमपी02 वीबी 2047 है। इसमें 'वीबी' का मतलब विकसित भारत है, जबकि '2047' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को दर्शाता है, जिसमें वर्ष-2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

पहले भी घटा चुके हैं काफिले की गाड़ियां

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इससे पहले भी ईंधन बचाने के लिए अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर चुके हैं। पहले काफिले में 13 वाहन चलते थे, जिसे घटाकर 7 कर दिया गया था। इसके बाद कई मंत्रियों और अधिकारियों ने भी कार-पूलिंग और कम वाहनों के उपयोग को अपनाया।

पहली बार काफिले में शामिल होगी इलेक्ट्रिक कार

मुख्यमंत्री के काफिले में पहली बार किसी इलेक्ट्रिक कार को शामिल किया जा रहा है। इसे सरकारी व्यवस्था में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए वाहन से जुड़े सभी जरूरी प्रोटोकॉल पूरे कर लिए गए हैं। ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने कार की जांच भी की है।

श्योपुर में आंधी-बारिश, पेड़ गिरने से 3 दबे, एक मौत

- **मैहर में बूंदाबांदी, इंदौर-उज्जैन समेत 36 जिलों में अलर्ट 60 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं**

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में ओले, बारिश और तेज आंधी के चलते हीटवेव (लू) का असर पूरी तरह खत्म हो गया है। बुधवार को श्योपुर में तेज आंधी और बारिश के बीच बस स्टैंड में 3 बाइक सवारों पर पेड़ गिर गया। दबने से एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। बारिश के कारण कॉलोनियों की सड़कें जलमग्न हो गई हैं।

वहीं मैहर में दोपहर के समय तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई।

मौसम विभाग ने नीमच, मंदसौर और आगर-मालवा जिलों में 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

मौसम विभाग भोपाल के अनुसार अगले चार दिनों तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। बुधवार को इंदौर और उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के 36 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बार नौतपा के पूरे 9 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश का दौर जारी रहा। कई जिलों में ओले गिरे।

- **पचमढ़ी सबसे ठंडा, भोपाल-ग्वालियर में 37 डिग्री रहा-** प्रदेश के 5 बड़े शहरों में तापमान में हल्की गिरावट देखी गई। भोपाल-ग्वालियर में 37 डिग्री, इंदौर में 38.2 डिग्री, उज्जैन में 37.5 डिग्री और जबलपुर में तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।खंडवा में पारा 40.1 डिग्री और खजुराहो में 40 डिग्री दर्ज किया गया। बाकी शहरों में तापमान इससे कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार, पचमढ़ी में सबसे कम 34.4 डिग्री, श्योपुर में 35 डिग्री, बैतूल में 35.2 डिग्री, शिवपुरी में 36 डिग्री, शाजापुर में 36.1 डिग्री, सतना-नर्मदापुरम में 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

इक नज़रिया, इक नज़र है शायरी
मरता है शायर, अमर है शायरी।
लुत्फ़ का बायस है यह ख़ुशज़ौक़ को
ख़स्त :दिल को चारागर है शायरी।
छा गया इक बार तो जाता नहीं
रूह पर ऐसा असर है शायरी।
जख़्म जिसको जितना भी गहरा मिला
उसकी उतनी पुरअसर है शायरी।
बस फ़ना होकर मिलेगा गर मिला
जी बहुत महँगा हुनर है शायरी।
अक़्ल वालों में न वो रह पाएगा
बन गयी जिसका जिगर है शायरी।
'अश्क' ख़ुद से हो शुरू, ख़ुद पर तमाम
रूह का ऐसा सफर है शायरी।

दिनेश मालवीय 'अश्क'

दिल्ली में आग ने 'लील' ली 21 जिंदगी

- **मालवीय नगर के 6 मंजिला होटल में भीषण अग्निकांड**
- **40 लोगों को बचाया गया, मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक**

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह फ्लरिश स्टे नाम के होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं। जो सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों से हैं। कितने विदेशी नागरिक मारे गए हैं, फिलहाल इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीयों लोगों के मुताबिक, मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8.50 बजे आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। घटना के वीडियो में कुछ लोग

जान बचाने के लिए जलती हुई इमारत की तीसरी-चौथी मंजिल से कूदते नजर आ रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे भी बिछाए थे। कुल 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई लोगों की हालत गंभीर है।

रेस्टोरेंट के ऊपर होटल था, आग 6 मंजिल तक पहुंची

आग 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने बी-एन-बी रेस्टोरेंट में लगी। कुछ देर बाद होटल में ऊपर की तरफ फैल गई। यह होटल दिल्ली के प्रेस एन्क्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स हॉस्पिटल और एम्स भी है। बताया जा रहा है कि इन अस्पतालों में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे।

अग्निकांड में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

मालवीय नगर होटल अग्निकांड केस में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक होटल में आने-जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था। अब होटल के फायर सेफ्टी एनओसी और सुरक्षा इंतजामों की जांच की जा रही है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रेस्तरां और ऊपर की मंजिलों पर होटल संचालित हो रहा था। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

6 रूम की परमिशन थी लेकिन 25 कमरे थे

फ्लरिस स्टे गेस्टहाउस को बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था। इसके तहत 6 रूम की परमीशन थी, लेकिन 25 कमरे बने थे। आग लगने के बाद होटल के रेस्टोरेंट के बेसमेंट में भी काफी लोग फंसे थे। इसमें अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता एक ही था, जो बहुत संकरा था। होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। आने जाने का एक ही रास्ता था।

हकीमपुर में बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भारी भीड़

- **बीएसएफ ने लाइन लगाकर चेक किए बायोमीट्रिक रिकॉर्ड**

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अवैध बांग्लादेशी अपने आप ही बॉर्डर पार जा रहे हैं। इसके कारण बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर काफी भीड़ देखी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बताया है कि इस चेक पोस्ट

पर करीब 300 बांग्लादेशियों की भीड़ पहुंची हैं। इन्हें बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद वापस भेजने की तैयारी की गई है। पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी के के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी भारत से लौट रहे हैं।

कंधों पर समान लेकर पहुंचे बॉर्डर- बुधवार को इसी कड़ी में बुधवार को उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट क्षेत्र में स्थित हकीमपुर बॉर्डर पर बांग्लादेश लौटने वाले लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। अधिकारियों के अनुसार, इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या लगभग 300 बताई जा रही है।

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

बंगाल में बड़ा 'खेला', टूट गई 'दीदी' की पार्टी

● ममता को बड़ा झटका, ऋतब्रत बनर्जी बने नेता विपक्ष ● विधानसभा स्पीकर ने दी मंजूरी, 60 विधायक हैं साथ!

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के बड़ा झटका लगा है। विधानसभा स्पीकर ने बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाया है। ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया है कि उनको 60 विधायकों का समर्थन हासिल है। टीएमसी से निकाले गए नेता संदीपन साहा ने कहा कि हमने अभी-अभी चिट्ठी सौंपी है। नेता प्रतिपक्ष के लिए तय कमरा आधिकारिक तौर पर अलॉट कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष अभी वहीं बैठे हैं। संदीपन साहा ने कहा कि हमारी इच्छा है कि ममता बनर्जी हमारी सलाहकार बनी रहें और हमें अपनी सलाह देती रहें, ताकि हम, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के साथ मिलकर, विधानसभा के अंदर पार्टी को प्रभावी ढंग से चला सकें।

पार्टी की बुरी हालत के लिए अभिषेक जिम्मेदारः संदीपन साहा

उन्होंने कहा कि पार्टी की जो बुरी हालत आज हो गई है, कुछ हद तक, वह अभिषेक बनर्जी की नाकामी है। आखिर, अगर जब सब कुछ अच्छा होता है तो आप उसका श्रेय लेते हैं, तो जब चीजें गलत होती हैं तो आपको उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। वहीं टीएमसी नेता प्रसून बनर्जी ने कहा ने कहा कि भाजपा के खिलाफ हमारा राजनीतिक संघर्ष बिना रुके जारी रहेगा। हमारी वैचारिक लड़ाई चलती रहेगी। इसके अलावा, जहां भी आवश्यक होगा, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में सरकार के साथ हमारा सहयोग भी जारी रहेगा।

अब भारत से अच्छे संबंध चाहता है तुर्की

साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइलें मिलने के डर ने बदले सुर, बढ़ाया दोस्ती का हाथ

अंकारा (एजेंसी)। तुर्की की रेसेप तैयप एर्दोगन सरकार के सुर भारत को लेकर बदल गए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने भारत से नाराजगी दूर करने और अच्छे संबंध बनाने की बात कही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत-तुर्की संबंधों के बीच में पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। तुर्की का यह बदला हुआ रुख तब दिखा है, जब तुर्की के कट्टर दुश्मन साइप्रस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें और कामिकाज ड्रोन खरीदने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने एक कार्यक्रम में भारत-तुर्की संबंधों पर हुए एक सवाल पर कहा, अगर भारत को इस बात से नाराजगी है कि हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं तो ऐसे तो कई देश हैं, जिनके इस्लामाबाद के साथ करीबी रिश्ते हैं। पाकिस्तान से रिश्ते को आपसी संबंधों के बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। फिदान ने आगे कहा कि द्विपक्षीय स्तर पर भारत के साथ हमारी कोई समस्या नहीं है। हम भारत से आग्रह करते हैं कि वह इस मुद्दे (पाकिस्तान) को किसी दूसरे नजरिए से ना देखे।

संक्षिप्त समाचार

डीके शिवकुमार बने कर्नाटक के नए सीएम

- संविधान हाथ में लेकर ली शपथ, 12 मंत्री भी बनाए
- जी परमेश्वर उपमुख्यमंत्री बने सिद्धा के बेटे भी मंत्री

बेंगलुरु (एजेंसी)। डीके शिवकुमार ने बुधवार को बेंगलुरु के लोक भवन में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवकुमार को 30 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया था। वे सिद्धारमैया की जगह राज्य की कमान संभालेंगे। उनके अलावा जी परमेश्वर ने नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। शिवकुमार के साथ 13 विधायकों ने भी शपथ ली। इनमें पूर्व सीएम सिद्धारमैया के एमएलसी बेटे यतींद्र सिद्धारमैया भी शामिल हैं।

सिद्धारमैया ने 28 मई को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। सिद्धारमैया 20 मई 2023 से 28 मई 2026 तक मुख्यमंत्री रहे। सोनिया गांधी ने शपथ लेने से पहले डीके शिवकुमार को फोन पर बधाई दी। कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक के नए सीएम डीके शिवकुमार की जमकर तारीफ की। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को मजबूत बनाने में शिवकुमार ने लगातार अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जब भी राज्य में पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है शिवकुमार ने हमेशा कांग्रेस को आगे बढ़ाने में मदद की है। उन्हें अपने राज्य के बाहर भी एक जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता है। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में भी है जो दूसरों के सुख-दुख में शामिल होते हैं। समारोह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शासन और पार्टी संगठन, दोनों में शिवकुमार की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का हर निवासी सिद्धा रमैया के कार्यकाल में राज्य की आर्थिक प्रगति और विकास पर गर्व महसूस करता है।

चंबल सैंक्चुरी में रात 12.59 बजे लोडर से रेत खनन

- सुप्रीम कोर्ट की रोक बेअसर
- खुर्द घाट का डेट-टाइम वाला सामने आया वीडियो

मुरैना (एजेंसी)। मुरैना जिले की चंबल सैंक्चुरी से अवैध तरीके से रेत निकालने का एक और वीडियो सामने आया है। यह वीडियो 2-3 जून की दरमियानी रात करीब 12.59

बजे महुआ थाना क्षेत्र के खुर्द घाट का बताया जा रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि लोडर मशीन से रेत निकाली जा रही है और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरा जा रहा है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने इसमें खनन का टाइम और डेट भी डाला है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद संबंधित विभागों में हलचल बढ़ गई है। देवरी घड़ियाल अभयारण्य के अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने बताया कि विभाग को वीडियो और अवैध खनन की सूचना मिली है। मामले की जांच के लिए वन विभाग और महुआ पुलिस के सहयोग से संयुक्त टीम रवाना की गई।

- **सुप्रीम कोर्ट ने अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के आदेश दिए हैं-** गौरतलब है कि चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सख्त रुख अपना चुका है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे प्रशासनिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।

सप्रे संग्रहालय में 'पुरखों को प्रणाम - पोस्टर प्रदर्शनी' व पुस्तक विमोचन

भोपाल। राज्यपाल मंगूभाई पटेल का कहना है कि आज तकनीकी सुविधाओं ने चीजों को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन आज से दो सौ साल पहले अभावों और अंगरेजों के आतंक बावजूद हमारे पूर्वजों ने किस तरह पत्रकारिता की थी, इस इतिहास से नई पीढ़ी को अवगत कराना बहुत जरूरी है।तभी वे पत्रकारिता के महत्व और दायित्व दोनों से परीचित हो सकेंगे।

राज्यपाल माधवराव सप्रे संग्रहालय में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों की श्रंखला में 'पुरखों को प्रणामपोस्टर प्रदर्शनी' तथा पुस्तक 'पीर पराई जाने रे' के विमोचन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ संपादक महेश श्रीवास्तव ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर मालती राय तथा राज्यपाल के प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी उपस्थित थे।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि यहां जो पोस्टर प्रदर्शनी लगी है उसमें हमारा गौरवशाली अतीत समाया हुआ है। इसे देखने के बाद हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा मन श्रद्धा से भर उठता है। उन्होंने सभी से प्रदर्शनी देखने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ संपादक महेश श्रीवास्तव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब हम त्यागी और बलिदानी संपादकों का स्मरण कर रहे हैं। ऐसी विभूतियों का स्मरण कर हम एक तरह से उनके ऋण से उऋण हो रहे हैं। उन्होंने सप्रे संग्रहालय से अपने निजी संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब भी वर्तमान समय का इतिहास लिखा जाएगा तो सप्रे संग्रहालय और उसके संस्थापक विजयदत्त श्रीधर का नाम प्रमुखता से लिखा जाएगा।

विशेष अतिथि महापौर मालती राय ने कहा कि आज जब हम पत्रकारिता के दो सौ साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं तब उन मनीषियों का स्मरण करना सुखद है जिन्होंने तमाम कठिनाइयों के बाद भी इस कार्य की पवित्रता को बनाये रखा था। इस अच्छे आयोजन के लिए महापौर ने सप्रे संग्रहालय की सराहना की।

राज्यपाल के प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी ने कहा कि हम पौराणिक काल की बात करें तो हमारे सामने दो ही पत्रकार हुए हैं, जिन्होंने सही सूचनाओं का आदान-प्रदान किया था। इनमें एक थे देवर्षि नारद और दूसरे महाभारत के संजय। लेकिन हम वर्तमान काल की बात करें तो तमाम बदलावों के बाद भी पत्रकारिता अपना धर्म निभा रही है।

आरंभ में संग्रहालय के संस्थापक निदेशक विजयदत्त श्रीधर ने स्वागत् वक्तव्य देते हुए कहा - आयोजन के पीछे प्रदेश के आठ करोड़ नागरिकों की ओर से कलम के पुरखों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भाव है। इस प्रदर्शनी में हमारे पूर्वज लेखकों और संपादकों से संबंधित जानकारी को संजोया गया है,जिससे आने वाली पीढ़ी इन मनीषियों के त्याग और साधना को समझ सकेगी। उन्होंने बताया कि अब यह प्रदर्शनी सप्रे संग्रहालय की दीर्घा का स्थायी हिस्सा होगी।

इस कार्यक्रम में पुस्तक 'पीर पराई जाने रे' का विमोचन किया गया। पुस्तक में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व को केंद्र में रखा गया है। पुस्तक की लेखिका शिल्पी दिवाकर ने बताया कि राज्यपालजी के साथ कार्य करते हुए मैंने यह अनुभव किया कि उनका जीवन एक साधना है। एक सामान्य परिवार से निकलकर यहां तक का सफर तय करने वाले राज्यपाल जी ने हमेशा दूसरों की पीड़ा को समझा है। उनके जीवन के इन सभी पक्षों का सार है यह पुस्तक 'पीर पराई जाने रे'।

आरंभ में संगहालय की ओर से विवेक श्रीधर, डॉ. अल्पना त्रिवेदी ने अतिथियों का स्वागत किया। राज्यपाल को संविधान सभा के सदस्यों की तस्वीर भी भेंट की गई। चित्रकार आलोक भावसार ने राज्यपाल की माताजी की चित्रकृति भेंट की तथा रक्शांना जाहिद ने सशक्त मप्र थीम पर तैयार पेंटिंग भेंट की। अंत में आभार प्रदर्शन डॉ. मंगला अनुजा ने तथा कार्यक्रम संचालन निदेशक अरविंद श्रीधर ने किया।

पति की पिटाई कर थाने पहुंची पत्नी, बोली-

वो बोल नहीं रहा, पुलिस ने आकर देखा तो हो गई थी मौत

छतरपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी और साले पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, ससुराल पक्ष का कहना है कि युवक शराब के नशे में आए दिन विवाद और मारपीट करता था। घटना वाले दिन भी उसने पत्नी के साथ मारपीट की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

शिवनगर कॉलोनी में हुई घटना

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 30 वर्षीय दीनदयाल कुशवाहा पुत्र करोड़ी कुशवाहा निवासी अनगौर थाना गुलगंज के रूप में हुई है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की शिवनगर कॉलोनी में हुई। बताया जा रहा है कि दीनदयाल की शादी करीब 12 वर्ष पहले नीलम कुशवाहा से हुई थी और दंपति के दो बच्चे भी हैं।

चार साल से मायके में रह रही थी पत्नी- मृतक के भाई ने बताया कि उसकी भाभी नीलम पिछले लगभग चार वर्षों से अपने मायके में रह रही थी। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। परिजनों के अनुसार इस मामले में आगामी 13 जून को कोर्ट में पेशी भी निर्धारित थी।

धमकियां मिलने का लगाया आरोप- मृतक के भाई का आरोप है कि पति-पत्नी के विवाद के दौरान पहले भी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दीनदयाल को फोन पर धमकियां दी गई थीं। उसने दावा किया कि नीलम पिछले दो वर्षों से छतरपुर में एक स्थान पर खाना बनाने का काम करती है और जिन लोगों के यहां वह काम करती थी, उन्हीं लोगों द्वारा उसके भाई को धमकाया जाता था।

बड़वानी में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

आंगनवाड़ी सहायिका की सैलरी जारी करने के बदले मांगी घूस

बड़वानी (नप्र)। प्रदेश के बड़वानी जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के एक परियोजना अधिकारी और भृत्य द्वारा कथित रूप से आंगनवाड़ी सहायिका का लंबित मानदेय जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए एक दलाल को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस मामले में एक अधिकारी और चपरासी को भी आरोपी बनाया गया है।

8 महीने से रुका था वेतन- लोकायुक्त इंदौर के पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम संगोदा बेडीपुरा निवासी उर्मिला सोलंकी की 17 सितंबर 2025 को आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के बाद से उन्हें लगभग आठ माह का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ था। आरोप है कि महिला एवं बाल विकास विभाग, परियोजना ठीकरी के परियोजना अधिकारी धन्नालाल दांगी और भृत्य दिनेश खतवासे ने आठ माह का लंबित मानदेय 52000 जारी करने के लिए 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।

रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी- उर्मिला सोलंकी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय इंदौर में की थी। शिकायत के सत्यापन में आरोप सही पाए जाने पर लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को ट्रैप दल गठित कर कार्रवाई की। लोकायुक्त के अनुसार भृत्य दिनेश खतवासे के कहने पर केरवा निवासी राजेश पाटीदार ने शिकायतकर्ता से पांच हजार रुपये की रिश्वत ली।

अमेरिका ने होर्मुज में ईरानी आईलैंड को बनाया निशाना

● ईरान का कुवैत-बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमला

तेहरान/वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद बीती रात सबसे बड़े सैन्य टकरावों में से एक देखने को मिला। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर हमले किए, जिससे युद्धविराम और परमाणु वार्ता दोनों पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तनाव तब शुरू हुआ जब अमेरिकी सेना ने खार्ग द्वीप के एक ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहे बोत्सवाना के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हेलफायर मिसाइल से हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि जहाज ने ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध और नाकेबंदी का पालन नहीं किया था। इसके जवाब में ईरान ने लाइबेरिया के झंडे वाले एक जहाज पर मिसाइलें दागने का दावा किया।

- **अमरीका ने ईरानी ऑयर टैंकरों पर हमले किए-** अमेरिका ने ईरान के केश्म आइलैंड, गोरुक और होर्मुज के पास ऑयल टैंकरों पर हमले किए। ईरान ने जवाब में एक जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया। ट्रम्प ने लेबनान में इजराइली हमलों पर नेतन्याहू को फोन पर फटकार लगाई। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा-अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। लेबनान में इजराइली हमले जारी हैं। नबातियेह समेत कई इलाकों पर एयरस्ट्राइक हुई, जबकि हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए।

सूर्या की मौत के बाद मदरसे पर चला बुलडोजर

- 850 जवान रहे तैनात, इलाके में किया फ्लैग मार्च

गाजियाबाद (एजेंसी)। सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। खोड़ा से करीब 15 किलोमीटर दूर मसूरी क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर एक मदरसे को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह मदरसा सरकारी

जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। इससे पहले सूर्या चौहान के इलाके खोड़ा में भी बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन बाद में अधिकारी उसे लेकर मसूरी क्षेत्र में पहुंच गए। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और रैपिड रिस्पांस फोर्स के 850 जवान पूरे इलाके में तैनात किए गए हैं। वहीं, प्रशासन अवैध निर्माणों और संपत्तियों की जांच में जुटा हुआ है। अब तक 1,600 से अधिक लोगों का सत्यापन किया जा चुका है और संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

दुनिया की आधी आबादी के भूखों मरने की नौबत

● जल्दी नहीं रुका ईरान युद्ध तो मच जाएगा हाहाकार ● चावल की कीमत में पिछले दो महीनों में भारी तेजी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान युद्ध को तीन महीने से ज्यादा समय हो चुका है और फिलहाल इसके खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के अधिकांश हिस्से में माइन बिछा दी है। इससे वहां से जहाजों की आवाजाही ठप पड़ी है। साथ ही ईरान ने बाब अल मंदेब को भी बंद करने की धमकी दी है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और यूरोप तथा एशिया के बीच ट्रेड का अहम रास्ता है। ईरान युद्ध के कारण दुनिया में तेल, गैस और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई टाइट होने से इनकी कीमत में काफी तेजी आई है। इससे दुनिया के भूखों मरने की नौबत आ गई है। ईरान युद्ध के बाद फर्टिलाइजर की कीमत में 50 फीसदी तेजी आई है। इसका सीधा असर खाने-पीने की चीजों खासकर चावल पर देखने को मिल रहा है। मई में एशियाई बेंचमार्क थाईलैंड वाइट प्राइस की कीमत में 20 फीसदी तेजी आई जो 2008 में आंकड़े रखने की शुरुआत होने के बाद एक महीने में आई सबसे ज्यादा तेजी है। अप्रैल से यह 26 फीसदी चढ़ चुका है। इसकी कीमत 480 डॉलर प्रति टन पहुंच चुकी है। इसी तरह शिकागो राइस फ्यूचर्स में भी पिछले महीने 15 फीसदी तेजी आई।

आधी आबादी का मुख्य आधार

दुनिया में आधी आबादी यानी 3.5 अरब से 4 अरब लोगों के मुख्य आहार चावल है। धान की फसल में फर्टिलाइजर का बहुत यूज होता है लेकिन आगे भी इसमें राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसकी वजह यह है कि फर्टिलाइजर्स की कीमत में आगे और तेजी आने की आशंका है। 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से थाईलैंड, कंबोडिया और फिलीपींस में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की कीमत में 50 फीसदी तेजी आई है। अमेरिका जैसे देश को भी वेनेजुएला से फर्टिलाइजर आयात करना पड़ रहा है क्योंकि ईरान युद्ध के कारण इसकी कीमत में काफी तेजी आई है। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल और गैस के साथ-साथ यूरिया और फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर्स आयात करने के लिए नए लाइसेंस जारी किए हैं।

जल जीवन मिशन पूरा करने केंद्र देगा 5000 करोड़

पीएचई की बैठक में सीएम बोले-अब ट्यूबवेल पर निर्भर न रहें, तालाब रिचार्जिंग बढ़ाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं रहनी चाहिए। सीएम ने पीएचई विभाग के अफसरों से कहा कि केवल ट्यूबवेल पर निर्भरता कम करनी होगी और तालाब-सरोवर निर्माण तथा जल रिचार्जिंग पर विशेष फोकस करना होगा।

साथ ही केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि मिलने जा रही है। जिससे मार्च 2028 से पहले प्रदेश में हर घर नल से जल का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

जल जीवन मिशन की प्रगति प्रदेश में जल जीवन मिशन का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उज्जैन राजस्व संभाग सहित 11 जिलों में शत-प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है। अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए हैं।

प्रदेश के 75 प्रतिशत परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। दिसंबर 2023 से अब तक 16.50 लाख से अधिक नए घरेलू नल कनेक्शन जारी किए गए हैं और 15,238 नए नलकूप व हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। 14,200 गांवों को पहले ही हर घर जल घोषित किया जा चुका है।

केन्द्र से मिलेंगे 5 हजार करोड़

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय से मध्यप्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत लगभग 5 हजार करोड़ रुपए का आवंटन मिलने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल द्वारा दी गई सहमति का स्वागत किया और अधिकारियों को केंद्र के साथ समन्वय तेज करने के निर्देश दिए। वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को 5 हजार करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन 2.0 की भी तैयारी शुरू कर दी गई है।

सीएम बोले- हवा में मत रहिए, हम भागीरथपुरा देख चुके हैं

पीएचई की बैठक में एसीएस मनीष रस्तोगी जब ये बता रहे थे कि जल जीवन मिशन के जरिए इतने गांवों में जल प्रदाय योजनाओं के काम हो चुके हैं। इसी दौरान सीएम ने कहा आप लोग ज्यादा हवा में मत रहिए पेयजल के साथ सीवेज प्रबंधन की भी चिंता कीजिए। हम अभी कुछ समय पहले भागीरथपुरा की स्थिति देख चुके हैं। मैं जब इंदौर जाता हूं तो सीवेज की गंदगी देखकर शर्म आती है।

जल निगम का नाम बदलेगा

बैठक में सीएम ने यह निर्देश दिए कि अब जल निगम का नाम जल एवं सीवेज प्रबंधन निगम होगा। अब पेयजल के साथ ही सीवेज प्रबंधन के कामों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

मेट्रोपॉलिटिन रीजन के लिए पानी प्रबंधन पर काम करो- बैठक में सीएम ने कहा कि इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटिन एरिया में जब क्षेत्र बढ़ेगा तो पानी की जरूरत बढ़ेगी। तब पानी कहां से लाएंगे। इसके लिए सरफेस वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाओ। दोनों मेट्रोपॉलिटिन रीजन में पेयजल, उद्योग और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता हो ऐसा प्लान बनाकर तैयार करो।

अदालत में फूट-फूटकर रोई गिरिबाला सिंह, कहा-

मीडिया ट्रायल से जान को खतरा, पुलिस और सीबीआई जानबूझकर कैमरों के आगे लाती है

भोपाल (नप्र)। विशेष सीबीआई अदालत ने एक चर्चित मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मां और बेटे को भोपाल सेंट्रल जेल में अन्य कैदियों से अलग बैरक में रखने का आदेश दिया है। दरअसल, सीबीआई ने इस बार आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। जांच एजेंसी का कहना था कि जब और जैसी जरूरत होगी, वे दोबारा रिमांड के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का फैसला सुनाया।

आरोपी महिला ने रोते हुए लगाए गंभीर आरोप- सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में उस वक्त माहौल बेहद गंभीर हो गया, जब आरोपी गिरिबाला सिंह ने जज के सामने अपना दर्द बयां किया। गिरिबाला ने कहा कि इस मामले में चल रहे मीडिया ट्रायल ने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि पहले स्थानीय पुलिस और अब सीबीआई, दोनों ही सिर्फ अच्छी मीडिया कवरेज दिलाने के लिए उन्हें पत्रकारों की भीड़ के आगे धकेल देते हैं। आरोपियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मीडिया ट्रायल से जुड़े आरोपों के बाद कोर्ट रूम के बाहर सुरक्षा कड़ी करने और जेल में आरोपियों को सुरक्षित व अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं।

क्राइम सीन री-क्रिएशन के बहाने तमाशा

महिला आरोपी ने अदालत को बताया कि जब जांच टीम उन्हें क्राइम सीन री-क्रिएशन के लिए उनके घर ले गई थी, तो जानबूझकर गाड़ी को घर से काफी दूर रोक दिया गया। उन्हें पैदल चलने पर मजबूर किया गया ताकि बाहर खड़ी मीडिया की भीड़ उन्हें आसानी से घेर सके और तस्वीरें खींच सके। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई की विशेष जज शोभना भालेवे ने तुरंत एक्शन लिया और कोर्ट रूम के बाहर जमा सभी मीडियाकर्मियों को वहां से हटने का हुक्म दे दिया।

एनएचएम संविदाकर्मियों की हड़ताल जारी

प्रदेशभर में कर रहे प्रदर्शन, बोले- मांगें नहीं मानीं तो 8 जून को सीएम आवास घेरेंगे

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत करीब 32 हजार संविदा कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल के बाहर बुधवार को भी कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया। वहीं, कई जगहों पर हड़ताल के कारण अस्पतालों में काम प्रभावित होने की सूचना भी मिली है।

संविदा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 8 जून को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वे सालों से स्वास्थ्य सेवाओं में जरूरी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। शिवराज सरकार में मांगों पर सहमति जताई गई थी, लेकिन बाद में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

प्रदेश के 52 जिलों में हो रही हड़ताल

संविदा कर्मी अजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के सभी 52 जिलों में हड़ताल जारी है। उनका आरोप है कि 2023 की संविदा नीति को प्रशासन सही तरीके से लागू नहीं कर रहा है। इसी के विरोध में कर्मचारी सार्वजनिक रूप से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेशभर में अलग-अलग तरीकों से अपनी आवाज उठा रहे हैं, ताकि उनकी मांगें शासन तक पहुंच सकें।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो सीएम आवास का घेराव करेंगे- संविदा कर्मी कामिनी मेहरा ने बताया कि सभी कर्मचारी 25 मई से हड़ताल पर हैं। 8 जून को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाई गई थी, लेकिन इसके बाद उस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है और सीएम आवास घेराव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

प्रदेश से राज्यसभा की रेस में कमलनाथ आगे

जातीय समीकरणों में अरुण, सज्जन और ब्राह्मण, क्षत्रिय नेता भी शामिल, 8 जून तक नॉमिनेशन होगा

भोपाल (नप्र)। एमपी में राज्यसभा की तीन सीटों पर नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जाएंगे। इनमें दो सीटों पर बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के कब्जे वाली सीट पर उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन तेज हो गया है।

कर्नाटक में नए सीएम डीके शिवकुमार के आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हो सकती है। दो दिनों में राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम तय होने की संभावना है।

खरगे और सोनिया ने कहा तो दिग्विजय जा सकते हैं- मौजूदा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह तीसरी बार राज्यसभा जाने से मना कर चुके हैं। अब सीनियर लीडर्स में पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम सबसे आगे है। हालांकि, कमलनाथ के मामले सोनिया गांधी की भूमिका सबसे अहम होगी।

कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि दिग्विजय के मामले में अंतिम फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी लेंगी। यानी अगर सोनिया खरगे ने कहा तो दिग्विजय तीसरी बार राज्यसभा जा सकते हैं।

जीतू भी समीकरण बनाने में जुटे

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भले ही सार्वजनिक तौर पर खुद को राज्यसभा की रेस से अलग कर चुके हों, लेकिन अंदरखाने वे पार्लियामेंट के अपर हाउस जाने के लिए जोड़-तोड़ लगा रहे हैं।

जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह पहले ही कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का करीबी बता चुके हैं। जीतू को प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का भी समर्थन हासिल है।

अब जातीय समीकरणों में नए चेहरों पर मंथन- कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्यसभा के लिए जातीय समीकरणों के हिसाब से भी नेताओं के नामों पर मंथन कर रही है। इस रेस में सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के नेताओं के नामों को खोजा गया है। अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा सहित करीब आधा दर्जन से ज्यादा नेता इस रेस में शामिल हैं।

अगर कमलेश्वर पटेल की बात की जाए तो 1996 में एनएसयूआई के जरिए वह राजनीति में आए। फिर युवा कांग्रेस में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कई अहम पदों पर रहे। दो बार विधायक और कमलनाथ सरकार में पंचायत मंत्री रहे हैं।

वर्तमान में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी (कांग्रेस वर्किंग कमेटी) के मेंबर हैं। विंध्य रीजन सहित पूरे एमपी में कुर्मी वोटर्स के सहारे राज्यसभा जाने के प्रयास में हैं

शायर बशीर बद्र के घर पहुंचे मंत्री धर्मेंद्र लोधी

पत्नी और बेटे के सामने पढ़ीं गजलें, याद में बड़ा सम्मान शुरू करने का ऐलान

भोपाल (नप्र)। उर्दू अदब की दुनिया के चमकते सितारे और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र की यादों को संजोने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सूबे के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने एलान किया कि राज्य सरकार जल्द ही बशीर बद्र की याद में एक नया साहित्यिक पुरस्कार शुरू करेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से बशीर बद्र का योगदान और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

परिजनों से मुलाकात के दौरान हुआ ऐलान

दरअसल, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी दिवंगत शायर के भोपाल स्थित ईदगाह कॉलोनी वाले आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने बशीर बद्र की पत्नी राहत बद्र और बेटे तैय्यब बद्र से मुलाकात की और पूरे राज्य की तरफ से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। इस भावुक मुलाकात के दौरान मंत्री ने बशीर बद्र की कुछ बेहद लोकप्रिय गजलें भी पढ़ीं और याद किया कि कैसे उनकी लिखी लाइनें सीधे लोगों के दिलों में उतर जाती थीं। मंत्री ने कहा बशीर बद्र साहब देश के सबसे चहेते शायरों में से एक थे। इस अवॉर्ड के लिए क्या मापदंड होंगे और चयन की प्रक्रिया कैसी होगी, इसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। यह पुरस्कार हमारी सरकार की तरफ से उनकी याद में एक स्थायी सम्मान होगा।

सीएम मोहन यादव की सहमति से लिया फैसला

मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ चर्चा के बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में तेजी से काम किया। बशीर बद्र ने अपनी शायरी से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए उनकी याद में यह अवॉर्ड शुरू करना उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरकार इस पुरस्कार के जरिए उर्दू और साहित्य जगत से जुड़े उन चेहरों को सम्मानित करेगी जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।

केरल हाईकोर्ट ने कहा- वायरल गर्ल बालिग

पति को एमपी में जमानत याचिका लगाने एक महीने की ट्रांजिट बेल दी, गिरफ्तार नहीं कर सकेगी पुलिस

भोपाल (नप्र)। केरल हाईकोर्ट ने वायरल गर्ल को प्रथम दृष्टया बालिग मानते हुए उसके पति को एक महीने की ट्रांजिट बेल दे दी है। अब एक महीने तक मध्य प्रदेश पुलिस उसके पति को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। वह अग्रिम जमानत के लिए मध्य प्रदेश की कोर्ट में याचिका लगा सकता है।

हाईकोर्ट के जज कौसर एडप्पागथ ने कहा- युवती के जन्म प्रमाणपत्र में उसके पैदा होने की तारीख 1 जनवरी 2008 दर्ज है, इसलिए वह बालिग है। इस पर मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दावा किया कि ये प्रमाणपत्र फर्जी है। असलियत में वायरल गर्ल नाबालिग है।

जज ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा- जन्म प्रमाणपत्र के अतिरिक्त आवेदक क्रमांक-2 (वायरल गर्ल) का वोटर आईडी और बैंक पासबुक भी कोर्ट में पेश किए गए हैं। जिनसे यह स्पष्ट होता है कि वह बालिग है। वह स्वयं भी बालिग होने का दावा कर रही है। वायरल गर्ल ने शपथपत्र भी दिया है कि उसने आवेदक क्रमांक-1 के साथ विवाह किया है।

अदालत ने वायरल गर्ल के पति की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वह 3 जून से एक महीने के भीतर मध्य प्रदेश की सक्षम अदालत में अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। इस अवधि के समाप्त होने तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

दलील- युवती हिंदू और युवक मुसलमान, मंदिर में शादी जायज नहीं- वायरल गर्ल और उसके पति ने अपनी संयुक्त याचिका में दावा किया था कि यदि वे मध्य प्रदेश जाते हैं तो अलग-अलग धर्मों से होने के कारण कट्टरपंथी तत्वों द्वारा उनकी ऑनर किलिंग की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि गिरफ्तारी से संरक्षण के आदेश के बिना वे न तो यात्रा कर सकते हैं और न ही मध्य प्रदेश में जमानत याचिका दायर करने के लिए किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं। वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया- युवती हिंदू है और उसका पति मुस्लिम, इसलिए मंदिर में हुआ उनका विवाह वैध नहीं है। इस आधार पर स्थानीय मैरिज रजिस्ट्रार को उन्हें विवाह प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं है।

फिल्म शूटिंग के दौरान हुई थी दोनों की मुलाकात- दरअसल, वायरल गर्ल की मुलाकात केरल में फिल्म शूटिंग के दौरान युवक से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और मार्च 2026 में दोनों ने शादी कर ली।

डायरेक्टर के खिलाफ केरल में दर्ज कराई थी एफआईआर

वायरल गर्ल ने 29 अप्रैल 2026 को डायरेक्टर सनोज मिश्रा और तीन अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर कराई थी। एफआईआर के बाद केरल की एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जब वह नाबालिग थी, तब डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। मिश्रा ने उसे एक्टिंग के मौके देने का झांसा देकर उसका शोषण किया। आरोपियों में केरल के विहिप नेता और वकील अनिल विलायल भी शामिल हैं। पीड़िता ने उन पर सोशल मीडिया पर बदनामी करने का आरोप लगाया है। दो अन्य आरोपियों के नामों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है।

फिल्म डायरेक्टर बोले- आरोप सोची-समझी साजिश- उधर, फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने इन आरोपों को सोची-समझी साजिश बताया है। दावा किया कि उन्हें लव जिहाद जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी फिल्म की अभिनेत्री को बहला-फुसलाकर केरल पहुंचाया गया। नाबालिग लड़की से फर्जी कागजों के आधार पर शादी की गई। अब मामले में आवाज उठाने पर उन्हें ही झूठे केस में फंसाया जा रहा है।

सॉरी मम्मी-पापा, दोबारा पेपर देने की हिम्मत नहीं

नीट पेपर लीक से टूटी मऊगंज की छात्रा ने खुदकुशी की, सामने आया सुसाइड नोट

मऊगंज (नप्र)। नीट 2026 की तैयारी करने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी का। आकांक्षा ने 20 मई को नागपुर में फांसी लगा ली। अब उसका सुसाइड नोट सामने आया है। इसमें लिखा है- पहले पेपर में अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद थी, लेकिन अब दोबारा अच्छा पेपर होगा, इसकी गारंटी नहीं है। सॉरी मम्मी-पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया। आकांक्षा मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली थी। गांव के एक छोर पर आकांक्षा के पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी का बड़ा सा घर है। उनके भाई दद्दी कुमार भी उन्हीं के साथ रहते हैं। घर के बरामदे में कुर्सियों पर परिवार के सदस्य बैठे हैं। दूसरी तरफ बोरियों में हाल ही में खेतों से आया अनाज रखा है। दो दिन पहले कृष्ण कुमार से मिलने कांग्रेस नेता आए थे। इसके बाद ही यह मामला मीडिया में आया।

पिता बोले- वह अब वापस नहीं आएगी- कृष्ण कुमार कहते हैं- कोई कुछ भी कह ले। हम जानते हैं हमारी बिटिया अब आने से रही। पढ़ाई में होशियार थी। बड़ी उम्मीद थी।

छिंदवाड़ा में महिला हेड कॉन्स्टेबल ने सुसाइड किया

सूने घर में जाकर खुद को लगाई आग

छिंदवाड़ा (नप्र)। छिंदवाड़ा के देहात थाना क्षेत्र स्थित प्रियदर्शनी कॉलोनी में बुधवार सुबह पुलिस लाइन में पदस्थ एक महिला प्रधान आरक्षक (हेड कॉन्स्टेबल) ने आत्महत्या कर ली। मृतका दीपा नेगी ने अपने सूने घर में जाकर खुद को आग के हवाले कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी अजय राणा और देहात थाना निरीक्षक जीएस राजपूत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतका डिप्रेशन की शिकार थीं और उनका नागपुर में इलाज चल रहा था।

संपादकीय

बालेन का बयान सियासी नासमझी

नेपाल के युवा प्रधानमंत्री और पूर्व में मशहूर रैपर रहे बालेन शाह द्वारा भारत और नेपाल द्वारा एक दूसरे की जमीन कथित अतिक्रमण और उसे सुलझाने को लेकर जिस तरह का विवादित बयान दिया है, वह यही साबित करता है कि उनमें राजनीतिक परिपक्वता की बेहद कमी है। शाह के बयान से जहां खुद नेपाल में भारी खलबली मची वहीं भारत ने उनके बयान और सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की ज़मीन पर अतिक्रमण किया है।दोनों पक्षों को बैठकर इस मामले को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि नेपाल पहले ही भारत को एक आधिकारिक कूटनीतिक नोट भेज चुका है और उसे जवाब भी मिल चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल ने सीमा विवाद को लेकर चीन और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी कूटनीतिक स्तर पर चर्चा की है।प्रधानमंत्री बालेन शाह के बयान पर अपनी अधिकृत प्रतिक्रिया में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा के कुछ हिस्से को लेकर मसले हैं, जिनको सुलझाना बाक़ी है। अपनी प्रेस ब्रीफिंग में रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने भारत-नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के पीएम के बयान और उनके विदेश मंत्रालय की टिप्पणी को सुना है। हालांकि भारत-नेपाल सीमा के 98 प्रतिशत हिस्से का निर्धारण हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं, जिनको सुलझाया जाना बाक़ी है। गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्ज़े और नो मैंस लेंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उनमें किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।'' यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शाह ने भारत नेपाल सीमा मसले को सुलझाने के लिए ब्रिटेन और चीन की मदद लेने की बात कही थी, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। उधर बालेन के बयान से खुद नेपाल में बवाल मच गया है। वहां के राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया यूज़र्स द्वारा बालेन शाह की तीखी आलोचना की जा रही है। नतीजतन नेपाल के विदेश मंत्रालय को पीएम के बयान पर सफ़ाई देनी पड़ी है। कई नेपाली राजनयिकों ने कहा कि बालेन शाह के इस बयान ने कालापानी, लिम्पियाधुरा और सुस्ता पर नेपाल के दावे को कमज़ोर कर दिया है। वहीं दक्षिण एशिया मामलों के जानकार प्रोफ़ेसर एसडी मुनि ने प्रधानमंत्री बालेन शाह की साफ़गोई की तारीफ़ की है। मुनि ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री बालेन शाह इस बात को साहस के साथ स्वीकार करने के लिए बधाई के पात्र हैं कि भारत-नेपाल सीमा विवाद एकतरफ़ा नहीं है। नदी के मार्ग में बदलाव के कारण नेपाल सुस्ता क्षेत्र में भारतीय भूभाग पर बैठा हुआ है।' हालाँकि, उन्होंने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश न करने की सलाह दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल जेन जी आंदोलन के बाद बीती पांच मार्च को हुए चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने प्रतिनिधि सभा में लगभग दो-तिहाई बहुमत हासिल कर बालेन शाह के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। लेकिन इस सरकार ने सत्ता में आते ही कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन पर उंगलियां उठ रही हैं।

तमिलनाडु की सियासत बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती

बीजेपी के भीतर भी इस बात को लेकर एक गंभीर आत्ममंथन चल रहा है कि अन्नामलाई का जाना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। राज्य के कई सीनियर नेताओं का दबी जुबान में मानना है कि दिल्ली में बैठे रणनीतिकार तमिलनाडु के जमीनी मिजाज और चुनावी नब्ज को ठीक से समझने में नाकाम रहे। अगर पार्टी ने अन्नामलाई को पूरी खुली छूट और फैसले लेने की आजादी दी होती, तो आज विजय राज्य में राजनीतिक परिवर्तन के अकेले नायक बनकर नहीं उभरते।

नजरिया

अजय कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

दक्षिण भारत के सियासी समर में तमिलनाडु इस वक्त एक बेहद दिलचस्प और जटिल मोड़ पर खड़ा है। कर्नाटक कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई की दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातों ने राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। चेन्नई एयरपोर्ट पर बिना बीजेपी के झंडे वाली गाड़ी से उतरने से लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ बंद कमरों में हुई बैठकों तक, हर घटनाक्रम इसी ओर इशारा कर रहा है कि यह रिश्ता अब एक 'म्युचुअल डिवोर्स' यानी आपसी सहमति से जुदा होने की कगार पर पहुंच गया है। करीब पांच साल का यह साथ दोनों ही पक्षों के लिए बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा है, जहां दोनों ने एक-दूसरे को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब इस रिश्ते की उम्र पूरी होती दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्नामलाई बीजेपी से कोई दुश्मनी या टकराव मोल लेकर नहीं, बल्कि एक बेहद 'खूबसूरत मोड़' पर हंसते-हंसते विदा होना चाहते हैं, ताकि भविष्य में कभी जरूरत पड़ने पर गठबंधन या साथ मिलकर काम करने के विकल्प हमेशा खुले रहें।

राजनीतिक गलियारों और सूत्रों के हवाले से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, उनके मुताबिक अन्नामलाई ने दिल्ली दरबार में साफ तौर पर पार्टी से अलग होने की इच्छा जताते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हालांकि, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता। यही वजह है कि जब अन्नामलाई अमित शाह से मुलाकात के बाद वापस चेन्नई लौटने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते में थे, तब उन्हें फोन करके दोबारा बातचीत के लिए वापस बुला लिया गया। शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि वह प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के अपने फैसले पर एक बार फिर ठंडे दिमाग से विचार करें। बीजेपी की तरफ से उन्हें मनाने के लिए राज्यसभा सीट तक का ऑफर दिया गया, जिसे अन्नामलाई ने बेहद शालीनता से ठुकरा दिया। दरअसल, अन्नामलाई ने हाईकमान के सामने बहुत स्पष्ट तौर पर दो ही विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प यह है कि उन्हें पूरी स्वायत्तता, असीमित अधिकार और कम से कम सात साल के एक लंबे कार्यकाल के साथ दोबारा तमिलनाडु बीजेपी की कमान सौंपी जाए। दूसरा विकल्प यह कि अगर पार्टी ऐसा नहीं कर सकती, तो उन्हें गरिमापूर्ण तरीके से अपनी अलग राजनीतिक राह चुनने की आजादी दे दी जाए।

अन्नामलाई का पूरा ध्यान इस वक्त तमिलनाडु की जमीनी हकीकत पर केंद्रित है। उनका तर्क है कि राज्य के मौजूदा सियासी मिजाज में किसी भी शुद्ध राष्ट्रीय पार्टी के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। वहां एक ऐसी नई और वैकल्पिक राजनीतिक ताकत की जरूरत है, जो जमीन से जुड़ी हो और तमिल अस्मिता के साथ-साथ तमाम तबकों की चिंताओं को सुनने का माद्दा रखती हो। सूत्रों की मानें तो अन्नामलाई सीधे कोई राजनीतिक दल घोषित करने के बजाय सबसे पहले तमिलनाडु में एक बड़ा गैर-राजनीतिक जनआंदोलन शुरू करने की तैयारी में हैं, जिसका नाम 'मक्कल शक्ति इयक्कम' यानी 'पीपुल्स पावर मूवमेंट' हो सकता है। यह आंदोलन 'राष्ट्रवादी तमिल दर्शन' की बुनियाद पर खड़ा होगा, जिसे बाद में चलकर एक मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक दल का रूप दिया जा सकता है। आगामी 7 जून को वह अपने तमाम समर्थकों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद उनकी आगे की रणनीति और इस नए सफर का आधिकारिक ऐलान होने की पूरी संभावना है।

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे तमिलनाडु के बदलते राजनीतिक समीकरण और हाल ही में उभरा एक नया 'शून्य' सबसे बड़ी वजह है। दरअसल, सिनेमा के पर्दे से सियासत के मंच पर आए सुपरस्टार सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 108 सीटें जीतकर राज्य के दशकों पुराने द्रविड़ समीकरण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। विजय की इस आक्रामक एंट्री ने सत्तारूढ़ डीएमके और मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके के पारंपरिक वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगाई है। अन्नामलाई को लगता है कि थलपति विजय के इस उभार के बाद द्रविड़ राजनीति का वह पुराना दौर अब खत्म हो चुका है, जहां सिर्फ भाषा और क्षेत्रीयता के पुराने ढर्रे पर चुनाव जीते जाते थे। इस वक्त विजय को काउंटर करने के लिए राज्य में कोई दूसरा बड़ा और जुझारू चेहरा नहीं है। ऐसे में नए प्रयोगों और चेहरों के लिए तमिलनाडु की धरती पर एक बड़ा स्पेस तैयार हुआ है, जिसे अन्नामलाई अपनी शर्तों पर भुनाना चाहते हैं।

बीजेपी के भीतर भी इस बात को लेकर एक गंभीर आत्ममंथन चल रहा है कि अन्नामलाई का जाना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। राज्य के कई सीनियर नेताओं का दबी जुबान में मानना है कि दिल्ली में बैठे रणनीतिकार तमिलनाडु के जमीनी मिजाज और चुनावी नब्ज को ठीक से समझने में नाकाम रहे। अगर पार्टी ने अन्नामलाई को पूरी खुली छूट और फैसले लेने की आजादी दी होती, तो आज विजय राज्य में राजनीतिक परिवर्तन के अकेले नायक बनकर नहीं उभरते। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अन्नामलाई की बेहद आक्रामक और लोकप्रिय 'एन मन्न, एन मक्कल' (मेरी भूमि, मेरे लोग) पदयात्रा ने राज्य की राजनीति का नक्शा बदल दिया था। करीब 200 दिनों तक चली और सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों को नापने वाली इस यात्रा की बदौलत ही 2021 के चुनाव में महज 3 फीसदी पर सिमटी बीजेपी का वोट शेयर 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 11 फीसदी तक पहुंच गया था। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय नेतृत्व ने अन्नामलाई को किनारे करते हुए नैनार नागेंद्रन को कमान सौंप दी, जिसके पीछे एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की मजबूरियां बताई गईं। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी का वोट शेयर 2026 में एक बार फिर गिरकर महज 3 फीसदी पर आ गया।

इस पूरी उठापटक ने अन्नामलाई के समर्थकों के भीतर इस भरोसे को और मजबूत कर दिया है कि उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक लोकप्रियता और वजूद, सूबे में बीजेपी की अपनी सांगठनिक ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। यही वजह है कि चुनावी हार के बावजूद अन्नामलाई लगातार सुर्खियों के केंद्र में बने हुए हैं। 2021 में करूर की अरावाकुरिची सीट से विधानसभा चुनाव हारने और 2024 में कोयंबटूर लोकसभा सीट पर शिकस्त मिलने के बाद भी उनकी प्रासंगिकता रत्ती भर कम नहीं हुई है। उनकी साफ-सुथरी छवि, प्रशासनिक अनुभव, सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख युवाओं और शहरी वोटरों के बीच बेहद लोकप्रिय है।

हालांकि, बीजेपी जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का 'ठप्पा' हटने के बाद अपनी नई स्वतंत्र पहचान बनाना अन्नामलाई के लिए किसी बड़े स्टार्ट-अप को शुरू करने जैसा ही जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण काम है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां राष्ट्रीय दलों से अलग होकर क्षेत्रीय दल बनाने वाले कद्दावर नेता बाद में अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष करते दिखे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का उदाहरण सबके सामने है, जो बीजेपी से अलग होकर सालों तक पदयात्राएं करते रहे लेकिन अंततः जनता के बीच से अपनी पुरानी छवि नहीं मिटा पाए और वापस बीजेपी में ही अपनी पार्टी का विलय करना पड़ा। अन्नामलाई के सामने भी यही सबसे बड़ा खतरा है कि क्या वह खुद पर लगे बीजेपी के रंग को उतारकर जनता को यह समझा पाएंगे कि उनका नया आंदोलन वाकई अलग और पूरी तरह तमिल अस्मिता को समर्पित है। बहरहाल, 41 वर्षीय युवा और ऊर्जावान अन्नामलाई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और समय उनके पक्ष में है। वह इस पूरी विदाई को मशहूर शायर बशीर बद्र के उस फलसफे की तरह जीना चाहते हैं, जिसमें कहा गया है कि 'दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों।' अब देखना यह होगा कि 7 जून को चेन्नई की धरती से वह कौन सा नया राजनीतिक शंखनाद करते हैं।

विकास की ऐतिहासिक भूलें और एथेनॉल का संकट

ऊर्जा संकट

निलेश देसाई

लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं।

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध, वैश्विक अस्थिरता और बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं ने दुनिया को एक बार फिर ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव के बीच भारत में इन दिनों 'एथेनॉल ब्लेंडिंग' (पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण) को ऊर्जा सुरक्षा के एक बड़े समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।पहली दृष्टि में यह पहल देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आयातित तेल पर निर्भरता में कमी और कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम प्रतीत होती है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या हम तेल आयात का बिल कम करने की जल्दबाजी में अपनी आने वाली पीढ़ियों का पानी, भूमि और खाद्य सुरक्षा दांव पर लगा रहे हैं?

यदि विकास के इतिहास को समग्र दृष्टि से देखें तो एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आती है। जब भी किसी तात्कालिक संकट के समाधान के लिए जल्दबाजी में कोई नई नीति लागू की गई, वह कुछ समय बाद स्वयं एक बड़े संकट का कारण बन गई। आज एथेनॉल के संदर्भ में भी हमें इसी ऐतिहासिक अनुभव से सीखने की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत के विकास इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ तत्कालीन समस्याओं के समाधान ने भविष्य में नई चुनौतियों को जन्म दिया।

हरित क्रांति – साठ और सत्तर के दशक में देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। रासायनिक उर्वरकों, संकर बीजों और अत्यधिक सिंचाई पर आधारित हरित क्रांति ने तत्कालीन भूख की समस्या का समाधान किया और भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। किंतु आज वही मॉडल मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, जैव विविधता के क्षरण, रासायनिक प्रदूषण और भूजल दोहन जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन चुका है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे जा चुका है।

नलकूप क्रांति – किसानों को मानसून की अनिश्चितता से बचाने के लिए नलकूपों और भूजल आधारित सिंचाई को प्रोत्साहित किया गया। कुछ दशकों बाद स्थिति यह है कि भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा दोहनकर्ता बन गया है और अनेक क्षेत्र 'डार्क ज़ोन' घोषित किए जा चुके हैं। आज एथेनॉल नीति के संदर्भ में भी यही प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। क्या हम ऊर्जा सुरक्षा की खोज में जल सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं?

आंकड़ों के पीछे छिपा जल संकट – भारत में वर्तमान में मुख्यतः पहली पीढ़ी (1 जी) के एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना, चावल और मक्का जैसी खाद्य फसलों का उपयोग किया जा रहा है। ये फसलें अत्यधिक पानी की मांग करती हैं। एक लीटर चावल आधारित एथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 10,790 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।एक लीटर गन्ना आधारित एथेनॉल के लिए लगभग 3,630 लीटर पानी खर्च होता है। एक लीटर मक्का आधारित एथेनॉल के लिए लगभग 4,670 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है।भारत के अनेक राज्य पहले से ही जल संकट का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान पेयजल तक का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे समय में पानी-गहन फसलों को ईंधन उत्पादन के लिए बढ़ावा देना दीर्घकालिक दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है।

जमीनी हकीकत- छोटे किसानों की आत्मनिर्भरता पर असर– भारत के लगभग 86 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है। एथेनॉल उद्योग की बढ़ती मांग और बाजार के आकर्षण ने खेती के स्वरूप में तेजी से बदलाव लाना शुरू कर दिया है।

खेती की विविधता का क्षरण – परंपरागत रूप से किसान अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां और पशुपालन को एकीकृत रूप से अपनाता था। इससे परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। आज नकदी फसलों और एकल खेती के विस्तार के कारण किसान स्वयं अपने भोजन के लिए बाजार पर निर्भर होता जा रहा है।

सामुदायिक सहयोग की परंपराओं का विघटन –ग्रामीण समाज में 'आदजी-पादजी' जैसी परंपराएं, जिनमें लोग एक-दूसरे के खेतों में श्रमदान करते थे, धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं। यंत्रीकरण और व्यावसायिक खेती ने सामुदायिक संबंधों को कमजोर किया है।

बीज संप्रभुता का संकट – देशी बीजों की परंपरा लगातार कमजोर हो रही है। किसान अब बाजार आधारित संकर बीजों, रासायनिक उर्वरकों और बाहरी आदानों पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। इससे खेती की लागत बढ़ती है और किसानों की ऋणग्रस्तता गहराती है।

भोजन बनाम ईंधन- एक उभरता हुआ संकट – एथेनॉल नीति का सबसे गंभीर प्रश्न 'भोजन बनाम ईंधन' का है। जब उपजाऊ भूमि और खाद्य फसलें वाहनों के लिए ईंधन उत्पादन में लगाई जाएंगी, तो खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। यदि किसान अधिक लाभ के कारण दालों और तिलहनों की खेती छोड़कर एथेनॉल हेतु उपयोगी फसलों की ओर आकर्षित होते हैं, तो भविष्य में देश को दालों और खाद्य तेलों के आयात पर अधिक निर्भर होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में विडंबना यह होगी कि हम पेट्रोलियम आयात का बिल तो घटा देंगे, लेकिन भोजन आयात का बिल बढ़ा लेंगे। इससे न तो वास्तविक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी और न ही संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होगा।

आगे का रास्ता- समग्र दृष्टि की आवश्यकता

- ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जल, भूमि और खाद्य सुरक्षा की कीमत पर हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ वैकल्पिक और दूरदर्शी कदम आवश्यक हैं।
- एथेनॉल उत्पादन को कृषि अपशिष्ट, जैविक कचरे और दूसरी पीढ़ी (2 प्रतिशत) के बायोफ्यूल तक सीमित किया जाए।
- गांव स्तर पर विकेंद्रीकृत बायोगैस और जैव-ऊर्जा मॉडल विकसित किए जाएं।
- ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और रागी जैसे कम पानी वाली मोटे अनाज की फसलों को प्रोत्साहित किया जाए।
- जल उपयोग, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभावों का समग्र मूल्यांकन किए बिना किसी भी विस्तारवादी नीति को लागू न किया जाए।
- नीति निर्माण में किसानों, वैज्ञानिकों, स्थानीय समुदायों और नागरिक समाज संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

विकास का वास्तविक अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि या आयात बिल में कमी नहीं है। विकास वह है जो प्रकृति, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करे। इतिहास हमें बार-बार चेतावनी देता रहा है कि तात्कालिक लाभ के लिए बनाए गए समाधान, यदि समग्र दृष्टि के बिना लागू किए जाएं, तो भविष्य में गंभीर संकट का रूप ले सकते हैं।

एथेनॉल नीति के संदर्भ में भी हमें यही सावधानी बरतनी होगी। अन्यथा आज जो ऊर्जा सुरक्षा का समाधान प्रतीत हो रहा है, वही कल जल संकट, खाद्य असुरक्षा और कृषि संकट के रूप में हमारे सामने खड़ा हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम विकास को केवल उत्पादन और उपभोग के चश्मे से नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों और प्रकृति के संतुलन की दृष्टि से भी देखें।

क्रश, सोना और सोना बाबू

कटाक्ष

निर्मल गुप्त

लेखक व्यंग्यकार हैं ।

आजकल सोने की खरीद को लेकर सरकारी समझाइश बड़े जोर से साइबर संसार में वायरल हो रही है। ऐसे समय में जब सोने को जरा -सा छू लेने भर से 1000-500 रूपये की स्वर्ण भस्म इस तरह ऊँगली से चिपकी चली आये जैसे कभी नटखट बच्चे की उँगलियाँ पर पकड़ी गई तितली के रंग चिपक कर आ जाते थे। लोग कह रहे हैं कि सोने को जी भर देख लेने पर आदमी की देह में स्वर्ण भस्म के अभाव में व्याप्त दुर्बलता खुद-ब-खुद समाप्त हो जाती है।

क्या वक्त आ गया है कि ताजातरीन जवान हुई पीढ़ी अपने क्रश को सोना या सोना बाबू कहने से कतराती हैं। कौन इतनी महंगी और सनसनीखेज चाहत एफोर्ड कर पायेगा?

झपटमारों के मुरादों भरे दिनों में जीवन कितना सरल हो चला है। दिन भर में किसी महिला के कान- नाक में एकाध टॉप्स या नोज़पिन खींच लो , बस हो गयी हफ्ते भर की अय्याशी भरी दिहाड़ी पूरी। अब मारे डर के शायद ही कोई महिला गले में खरे सोने का मंगलसूत्र पहनती है. सब रोलगोल्ड से मंगल मना लेती हैं.

सरकारी एडवाइजरी न आई होती तो हम सोने की चिड़िया वाले अतीत को वक्त -बेवक्त जुगाली करते अपने-अपने हिस्से का समय बिता ले जाते। सोने की चिड़िया एक अतिरंजित भावुकता है। किसी ने 5 ग्राम के वजन वाली हमिंग बर्ड तक को कभी सोने का होते किसी मिथकीय गाथा तक में नहीं पाया।

सोना हमेशा सोना ही रहा। आम आदमी की पहुँच से हमेशा उसी तरह बाहर जैसे गधे के सर से सींग. सिर्फ देवयोग अथवा दहेज़ के फ़ॉर्मेट में सहज प्राप्य। सोना जब तथाकथित रूप से तीन अंकों में हुआ करता था तब बंदे की कुल मासिक आमदनी अकसर दहाई के आंकड़े को मुश्किल से छू पाती थी।

पुराने समय में लोग नौलखा हार टाइप की बात अपने लोकगीतों में इसलिए कर लेते थे कि कल्पना के कुलांचे भरने में आखिर हर्ज़ क्या है। सोने की अब वाली कीमतों को सुनते हुए लोगों के समझ नहीं आता कि क्रेता -विक्रेता परस्पर किस मानक पैमाने की बात कर रहे है। बातचीत ग्राम की हो रही है या नेनो ग्राम की? अब तो वह दिन दूर नहीं जब जौहरी की दुकान पर लोग तराजू के पास माइक्रोस्कोप लेकर बैठेंगे और सूंघने मात्र का टैक्स चुकाकर आ जाएंगे।

वजन के अनुसर सोने की कीमत जानते हुए प्राय क्रेता का गला सूख जाता है और जेब बड़ी रीती- रीती सी लगने लगती है। अब भूलवश कोई सोने की चिड़िया किसी आकाशगंगा से उड़ कर हमारे ग्रह पर आ निकलें तो उसे मारने -पकड़ने की ऐसी मारक होड़ मचे कि दस बीस हज़ार वीडियो बहादुर तो उनकी उड़ान की रील सबसे पहले बनाने और डाउनलोड करने के चक्कर में अपनी जान सांसत में डाल बैठें।

सच तो यह है कि सोने की चिड़िया न कभी थी , न कहीं है। बस उसके नाम पर चलने वाली सिर्फ बतकही है। सरकारबहादुर का काम है आगाह करना , जनता का काम है पेट भर कर उसका मजाक उडाना। हंसी मजाक में अवसाद भरे दिन टल जाते हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

फूटी कौड़ी की किस्मत इतनी फूटी भी नहीं थी

निर्मल आनंद

रमेश रंजन त्रिपाठी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

प्रख्यात साहित्यकार बिमल मित्र ने साठ-सत्तर साल पहले एक हजार तीन सौ छत्तीस पन्नों के दो वॉल्यूम में प्रकाशित अपने वृहद् उपन्यास को शीर्षक दिया- 'खरीदी कौड़ियों के मोल'। बेहद प्रतिष्ठित रचनाकार द्वारा कौड़ियों को अपने उपन्यास की पहली और सबसे बड़ी पहचान यानी शीर्षक में स्थान देना कौड़ियों के लिए फख्र की बात तो है। फ़्लैश बैक में जाएं तो तीन हज़ार सालों से कौड़ी का उपयोग मुद्रा के रूप में होता रहा है। केवल कौड़ी ही नहीं, फूटी कौड़ी की भी, अत्यल्प ही सही, वैल्यू तो होती थी। तीन फूटी कौड़ी मिलकर एक साबुत कौड़ी बनती थीं। यानी फूटी कौड़ी की किस्मत इतनी फूटी भी नहीं थी। दस कौड़ियों की एक दमड़ी और दो हजार पाँच सौ साठ कौड़ियाँ एक रुपये के बराबर थीं। सोचिए, दस कौड़ियों की एक दमड़ी के लिए कुछ लोग अपनी चमड़ी जाने देने के लिए तैयार रहते होंगे तभी तो कहावत बनी होगी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कौड़ी की कीमत में अलग-अलग स्थानों में घट-बढ़ होती रही है, जैसे कि किसी देश की करेंसी के भाव दूसरे देशों में बदलते रहते हैं। कौड़ी बीस की संख्या का प्रतीक मानी जाती है। चार कौड़ी यानी अस्सी का एक गंडा। चार सौ को पण कहते हैं जो बीस कौड़ी के बराबर होता है। भले ही प्रशांत महासागर में मिलनेवाली कौड़ी इन दिनों कोई मान्य मुद्रा नहीं है लेकिन बोलचाल में अभी भी इनका चलन ज़िंदा है। 'एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूँगा' कहनेवालों की कमी नहीं। धार्मिक मान्यता है कि कौड़ी समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी जी की कृपा पाने में सहायक होती है। लक्ष्मी जी और कौड़ी दोनों के प्राकट्य में सागर की भूमिका होने से ऐसी अवधारणा बनी होगी। आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि लोगों को दो कौड़ी का समझनेवाले भी धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए कौड़ी की मदद लेते हों।

एक प्रकार के समुद्री घोंघे का खोल, जिसे संस्कृत में कपर्द कहते हैं, बोलचाल की भाषा में कौड़ी हो गया। मुहावरों की जमात में 'दूर की कौड़ी' की कद्र 'दो कौड़ी का' होने से ज्यादा होती है। कौड़ी कितनी भी तुच्छ हो, इसका इस्तेमाल शारीरिक श्रृंगार के लिए भी किया जाता है। पहनावे, घर की सजावट और हमारे देश के कुछ प्रांतों में वैवाहिक रीति रिवाजों में कौड़ी का उपयोग होता है। अफ्रीका में कौड़ियों की मुद्रा का चलन रहा है। डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेज़ कौड़ियाँ देकर गुलाम खरीदा करते थे। आकार के कारण 'मनी कौड़ी' और 'रिंग कौड़ी' नाम पड़े। 'कौड़ियों का द्वीप' कहलाने वाले मालदीव में कौड़ियाँ इकट्ठा की जाती थींऔर वितरण भारत से होता था।

कौड़ियों की सजावट वैल्यू ऐसी है कि कई लोग अपनी भाषा की सहायक जिह्वा को कौड़ी बोलों से अक्सर अलंकृत करते रहते हैं। चौपड़ और चौपड़जैसे खेलों में कौड़ी का उपयोग पांसो के रूप में होता है। शायद पांसे महंगे होते हैं इसलिए। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि 'दो कौड़ी की हैसियत' वाले कौड़ी का अधिक उपयोग करते हैं। यद्यपि किसी जमाने में सात हजार छह सौ अस्सी फूटी कौड़ियाँ एक रुपये के बराबर होती थीं लेकिन अब एक रुपये में इतनी कौड़ियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं। अर्थात फूटी कौड़ियाँ अब कौड़ियों के दाम नहीं मिलेंगी। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब कौड़ी एक मुद्रा थी, उस समय का रुपया आज के लगभग सौ से डेढ़ सौ रुपये के बराबर हुआ करता था।

कौड़ियों ने अपने मान-सम्मान को बुलंदियों पर पहुँचाने की बहुत कोशिश की। वे वस्तुओं के विनिमय में मुद्रा बनीं, इंसानों के सजधज के काम आईं, खेलों में सहयोगी का रोल निभाया, धार्मिक पूजा-पाठ में अपनी जगह बनाई, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में कौड़ी माता के मंदिर का आकर्षण बनीं लेकिन अपने ऊपर चस्पाँ तुच्छता के विशेषण से कभी मुक्त नहीं होपाईं। जैसे कुछ लोगों का व्यक्तित्व दीन-हीन होता है वैसे ही कौड़ी हमेशा दो कौड़ी की ही रही। संत कबीर ने कौड़ियों को माध्यम बनाकर सुंदर उपदेश दिया है-

रात गँवाई सोय के, दिवस गँवाया खाय।

हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाय।

(कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान अपने जीवन की रातें अज्ञानता में सोकर और दिन खाने-पीने में बिता देता है। हीरे के समान अनमोल जीवन को वह व्यर्थकी बातों में कौड़ियों के भाव गँवा रहा है।) यह दो कौड़ी की बात नहीं है कि कौड़ी की जानकारी रखनेवाले को दूर की कौड़ी पास नजर आने लगती है।

बदलते रिश्तों के दौर में विवाह की चुनौतियां

पितृसत्ता भी विवाह संस्था के संकट का एक प्रमुख आयाम है। भारतीय समाज लंबे समय तक पुरुष प्रधान व्यवस्था पर आधारित रहा है। विवाह के बाद महिला से अपेक्षा की जाती रही कि वह पति और उसके परिवार के अनुरूप स्वयं को ढाल ले। यद्यपि समय के साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अनेक परिवारों में आज भी पारंपरिक सोच विद्यमान है। शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए यह स्थिति कई बार संघर्ष का कारण बनती है। वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सजग हैं, जबकि परिवार की पारंपरिक अपेक्षाएं उनसे समझौते की मांग करती हैं। यह टकराव वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करता है। दूसरी ओर, पुरुष भी एक संक्रमणकालीन सामाजिक स्थिति से गुजर रहे हैं। उनसे पारंपरिक 'परिवार के पालनकर्ता'की भूमिका निभाने की अपेक्षा अब भी की जाती है, जबकि आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। बढ़ती बेरोजगारी, नौकरी का दबाव और आर्थिक असुरक्षा पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है।

सामयिक

ममता कुशवाहा

लेखक शिक्षक हैं।

कुछ समय पहले भोपाल में दिव्या शर्मा नामक युवती की संदिग्ध मृत्यु ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रारंभिक स्तर पर यह मामला एक सामान्य पारिवारिक विवाद या आत्महत्या जैसा प्रतीत हुआ, किंतु जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, इसके पीछे संबंधों की जटिलता, पारिवारिक दबाव, वैवाहिक असंतोष, पीढ़ियों के टकराव और सामाजिक अपेक्षाओं का एक व्यापक तानाबाना सामने आने लगा। यह घटना केवल एक व्यक्ति या एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज में विवाह संस्था के बदलते स्वरूप और उस पर गहराते अविश्वास का प्रतीक बनकर उभरी। आज जब ऐसे अनेक मामले समाचारों की सुर्खियां बन रहे हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि विवाह संस्था को केवल व्यक्तिगत संबंध के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में समझा जाए।

भारतीय सभ्यता में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं रहा है। इसे एक संस्कार माना गया है, जिसमें दो परिवारों, दो वंशों और दो सामाजिक इकाइयों का जुड़ाव निहित होता है। हजारों वर्षों से विवाह भारतीय समाज की सबसे मजबूत सामाजिक संस्था के रूप में स्थापित रहा है। संयुक्त परिवार, सामाजिक उत्तरदायित्व, बच्चों का पालन-पोषण, आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के हस्तांतरण का प्रमुख आधार विवाह ही रहा है। किंतु पिछले कुछ दशकों में इस संस्था की प्रकृति और उसके प्रति समाज के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वैश्वीकरण, शहरीकरण और शिक्षा के विस्तार ने व्यक्ति को पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाया है। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण ने पारिवारिक संबंधों की पारंपरिक संरचना को चुनौती दी है। पहले विवाह को जीवन की अनिवार्य और अंतिम व्यवस्था माना जाता था, जबकि आज इसे व्यक्ति की पसंद और संतुष्टि के आधार पर परखा जाने लगा है। यह परिवर्तन अपने आप में सकारात्मक है क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को महत्व मिला है, किंतु इसके साथ ही संबंधों की स्थिरता और दीर्घकालिकता पर भी प्रश्न खड़े हुए हैं।

आज विवाह संस्था के सामने सबसे बड़ा संकट विश्वास का है। पति-पत्नी के बीच विश्वास की कमी, संदेह, संवादहीनता और अहंकार की टकराहट संबंधों को कमजोर कर रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक ने जहां लोगों को जोड़ने का कार्य किया है, वहीं संबंधों में अविश्वास के नए कारण भी उत्पन्न किए हैं। मोबाइल फोन, चैट, सोशल मीडिया मित्रता और आभासी संबंध कई बार वास्तविक वैवाहिक संबंधों में तनाव का कारण बनते हैं। कई बार बिना पर्याप्त प्रमाण के संदेह संबंधों को उस बिंदु तक पहुंचा देता है जहां से वापसी संभव नहीं रह जाती। विवाह संस्था पर बढ़ते संकट का एक महत्वपूर्ण कारण बदलती सामाजिक अपेक्षाएं भी हैं। पहले विवाह में त्याग, समायोजन और धैर्य को विशेष महत्व दिया जाता था। आधुनिक समाज में व्यक्तिगत आकांक्षाएं और आत्मसंतुष्टि अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। व्यक्ति अपने जीवनसाथी से केवल भावनात्मक सहयोग ही नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक संतुलन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी अनेक अपेक्षाएं रखने लगा है। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं तो निराशा और असंतोष जन्म लेते हैं। परिणामस्वरूप छोटी-छोटी समस्याएं भी बड़े संघर्ष का रूप ले लेती हैं।

पितृसत्ता भी विवाह संस्था के संकट का एक प्रमुख आयाम है। भारतीय समाज लंबे समय तक पुरुष प्रधान व्यवस्था पर आधारित रहा है। विवाह के बाद महिला से अपेक्षा की जाती रही कि वह पति और उसके परिवार के अनुरूप स्वयं को ढाल ले। यद्यपि समय के साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अनेक परिवारों में आज भी पारंपरिक सोच विद्यमान है। शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए यह स्थिति कई बार संघर्ष का कारण बनती है। वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सजग हैं, जबकि परिवार की पारंपरिक अपेक्षाएं उनसे समझौते की मांग करती हैं। यह टकराव वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करता है। दूसरी ओर, पुरुष भी एक संक्रमणकालीन सामाजिक स्थिति से गुजर रहे हैं। उनसे पारंपरिक ÷परिवार के पालनकर्ता÷ की भूमिका निभाने की अपेक्षा अब भी की जाती है, जबकि आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। बढ़ती बेरोजगारी, नौकरी का दबाव और आर्थिक असुरक्षा पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। कई बार वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते और यह दमन वैवाहिक संबंधों में दूरी का कारण बन जाता है। इसलिए विवाह संबंधी समस्याओं को केवल महिला या पुरुष के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझना आवश्यक है। विवाह संस्था पर संकट का एक अन्य कारण संयुक्त परिवारों का विघटन है। पहले परिवार के बुजुर्ग संबंधों में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। पति-पत्नी के बीच उत्पन्न विवादों को परिवार के भीतर ही सुलझा लिया जाता था। आज अधिकांश शहरी परिवार एकल परिवारों में परिवर्तित हो चुके हैं। ऐसे में विवादों को संभालने वाला कोई अनुभवी मार्गदर्शक नहीं होता। परिणामस्वरूप छोटे मतभेद भी गंभीर संघर्ष में बदल जाते हैं। न्यायालयों में बढ़ते वैवाहिक मुकदमे और तलाक के मामलों की संख्या इसी सामाजिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है।

लेकिन विवाह संस्था पर संकट का अर्थ यह नहीं कि समाज विवाह-विरोधी हो गयाहै। वास्तव में लोग आज भी स्थायी और भरोसेमंद संबंध चाहते हैं। समस्या यह है कि आधुनिक जीवन की गति, प्रतिस्पर्धा और तनाव संबंधों के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा को सीमित कर रहे हैं। पति-पत्नी दोनों कार्यरत हों तो पारिवारिक जिम्मेदारियों का संतुलन एक नई चुनौती बन जाता है। यदि कार्य-विभाजन और पारस्परिक सहयोग का भाव न हो तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। दिव्या शर्मा जैसे मामलों की चर्चा करते समय मीडिया और समाज को भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। किसी भी घटना को केवल अपराध-कथा के रूप में प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है। ऐसी घटनाओं के पीछे छिपे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों की पड़ताल अधिक आवश्यक है। यदि हम केवल दोषी और पीड़ित की खोज तक सीमित रह जाएंगे तो उन संरचनात्मक समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे जो ऐसी त्रासदियों को जन्म देती हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो ये घटनाएं विवाह संस्था में हो रहे गहरे परिवर्तनों की चेतावनी हैं।

मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न उठाना भी जरूरी है। भारतीय समाज में आज भी अवसाद, चिंता और वैवाहिक परामर्श जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा नहीं होती। अनेक लोग मानसिक तनाव से गुजरते हैं, लेकिन सहायता लेने में संकोच करते हैं। यदि विवाह पूर्व और विवाहोत्तर परामर्श की संस्कृति विकसित हो, तो कई समस्याओं का समाधान प्रारंभिक स्तर पर ही संभव हो सकता है। विकसित देशों में पारिवारिक परामर्श एक सामान्य प्रक्रिया है, जबकि भारत में इसे अभी भी सामाजिक कलंक की दृष्टि से देखा जाता है। वर्तमान समय में विवाह संस्था को बचाने का अर्थ पुराने मूल्यों की अंधी पुनर्स्थापना नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि विवाह को समानता, सम्मान, संवाद और साझेदारी के आधुनिक मूल्यों के आधार पर पुनर्परिभाषित किया जाए। पति-पत्नी का संबंध अधिकार और नियंत्रण का नहीं, बल्कि सहयोग और विश्वास का होना चाहिए। परिवारों को भी यह स्वीकार करना होगा कि नई पीढ़ी की आकांक्षाएं और जीवनशैली पहले से भिन्न हैं। वहीं नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि किसी भी दीर्घकालिक संबंध की सफलता केवल प्रेम से नहीं, बल्कि धैर्य, संवेदनशीलता और निरंतर संवाद से सुनिश्चित होती है।

वर्तमान में विवाह संस्था पर बन रहे विषवृत्त केवल किसी एक घटना या एक परिवार की कहानी नहीं हैं। वे उस सामाजिक संक्रमण की अभिव्यक्ति हैं जिससे भारतीय समाज वर्तमान में गुजर रहा है। दिव्या शर्मा जैसी घटनाएं हमें यह सोचने के लिए बाध्य करती हैं कि कहीं संबंधों की नींव में विश्वास, संवाद और सहानुभूति का क्षरण तो नहीं हो रहा। यदि समाज, परिवार और राज्य मिलकर इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करें, तो विवाह संस्था को अधिक मानवीय, समानतामूलक और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अन्यथा संबंधों के टूटने, अकेलेपन और अविश्वास का यह दुष्चक्र केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करता रहेगा। विवाह की वास्तविक शक्ति किसी कानूनी अनुबंध में नहीं, बल्कि उन मानवीय मूल्यों में निहित है जो दो व्यक्तियों को जीवन की हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने की प्रेरणा देते हैं।

बारिश की बूंदों में अपना भाग्य ढूंढता है आदमी

विचार

विवेक कुमार मिश्र

लेखक हिंदी के प्रोफेसर हैं।

भीगी सड़कों पर चलने का अलग सुख होता है, जब शुरुआती बारिश में सड़कें भीगती हैं तो एक अलग ही तरह का दृश्य बनता है। सड़कें गीली होती हैं, जीवन की तरह ही रसमय हो जाती हैं, अंगारे सी तप रही सड़कों पर ठंडक का जब अहसास हो तो फिर क्या कहने। हवा में ठंडक, सड़क पर ठंडक और आंखों में बारिश की नमी के साथ ही एक राहत की दुनिया महसूस होने लगती है। इन बारिश की बूंदों में आदमी अपने भाग्य को ढूढ़ता है, बारिश के साथ ही खेत खलिहान संभालते किसान दिख जाते हैं, उनके लिए बादल राग हो जाता है वे खिलते और खुश हो जाते हैं। बारिश और बादलों का साथ ऐसा बनता है कि सब मगन होकर नाचने गाने लगते हैं। ऐसे में निराला की बादल राग कविता का ध्यान आता है कि कैसे आमजन, जो छोटे हैं वे बादल का किस तरह से स्वागत करते हैं -

हिल हिल,
खिल-खिल
हाथ हिलाते
तुझे बुलाते,
विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते

जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर
तुझे बुलाता कृषक अधीर ,
ऐ विप्लव के वीर।
बादल राग - निराला

ये कविता बारिश और बादलों को उन किसानों द्वारा स्वागत के रूप में गाया गया है जिनके जीवन का आधार ही बारिश और प्रकृति के बीच रचा बसा होता है। बारिश के साथ ही अगली फसलों की तैयारी शुरू हो जाती है, रुकें हुए काम गति पकड़ लेते हैं।

बारिश से बचकर आप जीवन की बातें नहीं करते, जीवन से संवाद करने के लिए जीवन संसार में, मौसम के बीच खुले मैदान में जाकर ही आप सही ढ़ंग से संसार को देख समझ सकते हैं। आसमान से धीरे-धीरे बारिश की बूंदें उतर रही हैं इससे पहले चारों तरफ बादलों का घेरा बना जाता है। आसमान में बादल हों तो एक न एक आकृति बनती जाती है हिलते डुलते तेज गति में हवाओं के साथ तैरते बादलों को देखने का भी सुख है। जीवन पथ पर प्रकृति के साथ संवाद करते हुए ही आप सही ढ़ंग से संसार में चलते हैं। एक एक कर बारिश की बूंदे टप टप आसमान से धरती पर उतर रही हैं । बारिश की बूंदों के साथ ही मौसम खुशनुमा बन गया है। सब खुश होकर बाहर आ जा रहे हैं, जो नवतपा की आंच थी जो रातें भी आग भरी हवा फेंक रही थी वह शाम से ही खुशनुमा माहौल रच दी है। प्रकृति की सत्ता कितनी बड़ी है कि एक ही क्षण में सबकुछ बदल देती है। प्रकृति के स्पंदन में सबके लिए जगह होती है। यदि ठंडी हवाएं चल रही हैं तो सबके लिए समान रूप से चल रही हैं। ये हवाएं किसी अमीर के यहां आकर रुक नहीं जाती न ही किसी को परेशान करती हैं यदि कोई एक इनके साथ सुखी हो सकता है तो फिर सब सुखी और मगन हो जाते हैं। प्रकृति के इस क्रम को, प्रकृति के जीवन को जीने के लिए अपने घरों से बाहर निकल कर आना होगा , प्रकृति को रंगते चहकते और चमकते हुए देखना होगा । अपनी आंखों का विस्तार करना होगा । प्रकृति हमें नये सिरे से सोचने के बारे में कहती है। प्रकृति के आंगन में देने के लिए इतना कुछ होता है कि सबकी झोली भर जाती है। आंखों को सुख और जीवन में राहत महसूस यदि कहीं जाकर होती है तो वह प्रकृति के विस्तार में ही है। मनुष्य का प्रकृति के साथ समन्वय का रिश्ता है। वह उसके साथ ही चलता है। यहां पर विनम्र होकर प्रकृति को मां समझकर जीवन को संचालित करता पड़ता है। प्रकृति के सामने एक क्षण के लिए भी अहंकार की सत्ता नहीं चलती प्रकृति की शक्तियां जब चलती हैं तो उसके सामने हम सबकी सत्ता होती ही कहां हैं एक पल में वह सब कुछ को उलट पलट कर रख देती है। वह बार बार यहीं कहती और सीखाती है कि मेरे सामने विनम्र होकर आओ सबकुछ मिलेगा लेकिन यदि अपनी सत्ता भूलकर आते हो या मद में आते हो तो फिर प्रकृति के सामने एक क्षण भी तुम्हारी सत्ता नहीं टिकेगी। प्रकृति को तो जतन से उसके बीच ही जाकर समझा जा सकता है। वह जीवनदायिनी सत्ता है। प्रकृति का ही एक रूप बादलों के बीच दिखता है। यहां से जीवन के प्रति राग व संसार को समझने की दृष्टि मिलती है।

बादलों को चलते हुए देखिए कैसे आसमान में दौड़ते हैं। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में काले भूरे बादल भागते रहते हैं और इन्ही के साथ हवा पानी और पानी की बूंदें लेकर धरती पर आ जाते हैं। हम सब बादल और आकाश को देखते हुए जीवन संसार को समझने की कोशिश करते हैं। जो कोई बादलों को नहीं देखा आकाश को नहीं देखा वह भला जीवन और माटी को कैसे देखेगा। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, ये बारिश की बूंदें सच में जीवन की बूंदें होती हैं धरती में समा जाती हैं। पेड़ पौधे सभी के साथ इन बारिश की बूंदों का एक रागात्मक रिश्ता दिखता है। बारिश की इन बूंदों के साथ ही दुनिया में एक नई चमक दिखने लगती है।

गुजरे जमाने की परीक्षाएं और परीक्षाफल

मुद्दा

रमेशचंद्र शर्मा

स्वतंत्र लेखक

वैसे तो बीते जमाने में परीक्षाएं प्रायमरी,मिडिल कक्षाओं के अलावा नवमी और दसवीं कक्षाओं में भी होती थीं मगर वे लोकल एक्जाम कहलाती थीं।छात्रों को ग्यारहवीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा का सामना करना होता था। जिसकी अपनी धमक होती थी।यह कहा जाता था , बेटा,बोर्ड की परीक्षा है कोई हंसी मजाक नहीं है। नतीजन जो विद्यार्थी लोकल एक्जाम हंसते खेलते पास कर लेता था बोर्ड परीक्षा के नाम से माथे पर पसीना आ जाता था।लिहाजा वह साल भर संजीदगी से क्लासेस अटेंड करता।पढ़ाई करता था।परीक्षाओं के दौरान तो खुद को पूरी तरह झोंक देता था। बोर्ड की इम्तहान और नतीजे दअरसल होते भी टफ थे। उस जमाने में छात्र जानते ही नहीं थे कि पेपर लीक क्या होता है? इम्तहान पास करने जा कोई शॉर्टकट नहीं हुआ करता था।बस ,एक ही रास्ता था कि पढ़ो,पढ़ो और पढ़ो।हां,एक काम जरूर होता था कि प्रिपरेशन लिव के पहले हर विषय के टीचर अपने हिसाब से छात्रों को आय एम पी सवाल जरूर बता देते थे।जो वे अपने अनुभवों पर आधारित होते थे।ये सवाल बताते वक्त वे छात्रों को चेता देते थे, इन सवालों के भरोसे ही मत रहना।कोर्स पूरा पढ़ना।जरूरी नहीं कि जो आय एम पी बताएं है वो आ ही जाएं ये बोर्ड की परीक्षा है।पूरे कोर्स में कहीं से भी सवाल आ सकते हैं।

खैर ,इम्तहान हो जाते थे।मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट में रिजल्ट आ जाते थे।बोर्ड के इम्तहान के रिजल्ट सभी अखबारों में छपते थे।जिस दिन के अखबारों में रिजल्ट आते थे अखबारों के करीबन सारे पन्ने रोल नंबरों से भरे होते थे।रिजल्ट शीट अखबारों के दफ्तर में एक दिन पहले ही आ जाती थी।लड़के

अखबारों के ऑफिसों में जाकर रिजल्ट जानने की जुगाड भिड़ाते थे। उस शाम अखबार जा सारा स्टाफ वीआईपी हो जाता था।जिस लड़कर की जान। पहचान होती उसकी पर्ची पर रिजल्ट मिल जाता था। आजकल जिस तरह से मैरिट लिस्ट के छात्रों के फोटो और अखबारों के द्वारा इंटरव्यू छापे जाते थे।वो सब उस जमाने में नहीं होता था।अगले दिन अखबारों में मेरिट लिस्ट प्रमुखता से प्रकाशित होती थी।तब ही जाकर छात्रों को पता लगता था कि वे मैरिट लिस्ट में आए हैं।मुझे याद है मेरा हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आया था अखबार के दफ्तर में काम करने वाले एक पत्रकार साहेब ने यह तो बता दिया था कि तू प्रथम श्रेणी ने पास हुआ था।जिसकी मुझे पूरी उम्मीद थी।मगर मैं मैरिट लिस्ट में आया हूं यह तो अगले दिन अखबार से ही मुझे पता पड़ा।मैरिट लिस्ट में आना और वह भी आर्ट विषय से यह मेरे लिए किसी सपने की तरह था।इस उपलब्धि को लेकर मेरे से बात करने कोई अखबार वाला नहीं आया।ना मुझे यह इल्म था कि अखबार में मैरिट लिस्ट वालों का साक्षात्कार वह भी सचित्र प्रकाशित होता है।हो सकता उन दिनों यह सब चलन ना भी हो।

बहरहाल,आज जब आए दिन पेपर लीक होने की खबरें आती है तो बड़ा बुरा लगता है।छात्रों के खुदकुशी के समाचार पढ़ कर यही सवाल मन में उठता है कि कोई भी इम्तहान जिंदगी में आखिरी कैसे हो सकता है? क्या जिंदगी की वैल्यू सिर्फ एक परीक्षा पास कर लेने तक ही सीमित होती है? हमारे जमाने में तो लड़का तीसरे नंबर से पास हो जाता था तो मातापिता कहते थे डिविजन का क्या छोरा पास तो हो गया अगली क्लास में तो चला गया,बात खत्म।सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास पास होने पर कहा जाता था ,क्या बोले रे पेला नंबर पास हुई गयो है।चलो, अच्छी बात है।

सच बताऊं,मैरिट लिस्ट में आने के पहले तो मुझे भी पता नहीं था कि मैरिट लिस्ट किस चिड़िया को कहते हैं। पढ़ते वक्त इतना ही जानते थे कि भई,परीक्षा पास करनी है इसलिए पढ़ना है।

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून

जल संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है । मालवा के हर शहर-कस्बे से लेकर हर प्रदेश में पानी को लेकर हाहाकार मचा है । बुरहानपुर के एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है जिसमें छोटी छोटी बच्चियाँ जोखिम के साथ गहरे कुएं से गंदा पानी उलीचती नजर आ रही है। इंदौर में पानी को लेकर विधायक-मंत्री का घेराव करती बेबस जनता की आवाज बेअसर नजर आ रही है । आज सोशल मीडिया पर पानी बचाने के संदेश तो बहुत नजर आते है मगर जमीनी स्तर पर पानी बचाने के दृश्य कम नजर आते है । पानी हमारे जीवन के लिए एक ऐसी ही जरूरी चीज है जो यों तो हमे ईश्वर प्रदत्त है,आज बहुतायत से उपलब्ध भी है मगर दिनों दिन बदलते पर्यावरण चक्र,कम होती बारिश, सूखते जलाशयों और दिनोंदिन गिरते भूजलस्तर को देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब पानी हमारे लिए बेहद कीमती हो जाने वाला है । पानी का मोल हमें तब समझ आता है जब हमारी जरूरत के समय पानी उपलब्ध नहीं होता । फिर बोरिंग या जलस्रोत सूख जाने के कारण हो या नल न आने के कारण ।

जलसंकट

मोहन वर्मा

लेखक पत्रकार हैं।

एक बहुत ही मशहूर ग़ज़ल की बेहद खूबसूरत पंक्तियाँ है-दुनिया जिसे कहते है जादू का खिलौना है,मिल जाये तो मिट्टी है खो जाये तो सोना है । यदि यहां दुनिया की जगह हर उस किसी भी चीज को रखकर देखें जो मिल जाने पर हम उसकी कदर नहीं करते है और खो जाने पर बैचेन हो जाते है तो हम समझ सकते है कि समय रहते हर चीज की कद्र करना कितना जरूरी है।ऐसी ही ज़रूरी शै है पानी। कवि रहीम ने सैकड़ों साल पहले अपने दोहे में कहा था- रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती, मानुस, चून ...

43 से 46 डिग्री चढ़ते तापमान के साथ साथ जल संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है । मालवा के हर शहर-कस्बे से लेकर हर प्रदेश में पानी को लेकर हाहाकार मचा है । बुरहानपुर के एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है जिसमें छोटी छोटी बच्चियाँ जोखिम के साथ गहरे कुएं से गंदा पानी उलीचती नजर आ रही है। इंदौर में पानी को लेकर विधायक-मंत्री का घेराव करती बेबस जनता की आवाज बेअसर नजर आ रही है । आज सोशल मीडिया पर पानी बचाने के संदेश तो बहुत नजर आते है मगर जमीनी स्तर पर पानी बचाने के दृश्य कम नजर आते है । पानी हमारे जीवन के लिए एक ऐसी ही जरूरी चीज है जो यों तो हमे ईश्वर प्रदत्त है,आज बहुतायत से उपलब्ध भी है मगर दिनों दिन बदलते पर्यावरण चक्र,कम होती बारिश, सूखते जलाशयों और दिनोंदिन गिरते भूजलस्तर को देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब पानी हमारे लिए बेहद कीमती हो जाने वाला है । पानी का मोल हमें तब समझ आता है जब हमारी जरूरत के समय पानी उपलब्ध नहीं होता । फिर बोरिंग या जलस्रोत सूख जाने के कारण हो या नल न आने के कारण ।

अभी किसी समाचार पत्र में एक खबर पढ़ी थी कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन को दुनिया का पहला जलविहीन शहर घोषित किया गया है क्योंकि वहां की सरकार ने अप्रैल 23 के बाद पानी की आपूर्ति करने में असमर्थता दिखाई है। वहां नहाने पर रोक लगाई गई है और 10 लाख से अधिक कनेक्शन कटे गये है। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पम्प जाकर पेट्रोल खरीदा जाता है वैसे ही वहां टैंकरों से अधिकतम 25 लीटर पानी देने की तेयारी है। अगर तो ये खबर सच्ची है तो स्थिति की भयावहता और आने वाले कल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है पानी की आने वाले सालों में कमी,गिरते जलस्तर और पानी बचाने की तमाम चेतावनियों के बावजूद आम लोगों में पानी बचाने और पानी का दुरुपयोग रोकने को लेकर जरूरी जागरूकता नज़र नहीं आती आज भी आये दिन ऐसी खबरें हमारे सामने आती रहती है जो पानी की परेशानी से रोजाना दो दो हाथ करती महिलाओं और बेटियों की बड़ी संख्या के बारे में हमें चेताती है जो कई कई किलोमीटर दूर से परिवार के लिए दो बर्तन पानी लाने को मजबूर है ।

पर्याप्त पानी होने पर जो लोग गाड़ी धोते,ब्रश या शेव करते समय,या बिना कारण पानी का दुरुपयोग करते है उन्हें यह बताना प्रासंगिक होगा कि मुंबई जैसे महानगर के नब्बे वर्षीय आबिद सूरती हर रविवार अपने जैसे सीनियर सिटीजन्स की टीम के साथ हर घर का दरवाजा खटखटाते है और पूछते है कहीं नलों से पानी टपकने की शिकायत तो नही है । और जवाब हां में आने पर उनकी टीम निशुल्क नल दुरस्त करके एक एक बूंद पानी बचाने का पुण्य काम कर रही है । आज से नहीं बरसों से । क्या इससे सबक नहीं लिया जा सकता ?

भूजलविदों के अनुसार देश के 21 से अधिक बड़े शहर ग्राउंड वाटर की समाप्ति के कगार पर है। सन 2050 तक पानी की मांग इसकी पूर्ति से अधिक हो जाएगी यानी अगले 25 साल बाद पानी को लेकर बड़ा संकट खड़ा होने के आसार है।कृषि, उद्योग, बिजली और सबसे पहले घरेलू जरूरतों के लिए पानी बेहद आवश्यक है । आज जल संरक्षण और जल संचयन के साथ पानी का पुनरुपयोग प्राथमिकता पर किया जाना जरूरी है

आज भले हमें पर्याप्त पानी उपलब्ध हो मगर देश के कई हिस्सों में पानी की कमी और पृकृति प्रदत्त अनमोल पानी के लिए जूझते और संघर्ष करते लोगों के समाचारों को पढ़कर तो हमें आने वाले समय के लिए सचेत होने की जरूरत है । यहाँ वहां बेकार बहते बेतहाशा पानी को देखकर अनदेखा करने का समय नहीं हैं। न केवल पानी बल्कि पेड़, नदी, जंगल, पहाड़,जैसी प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण की भी जरूरत है। विकास के नाम पर खड़ी सीमेंट की अट्टालिकाएं, कटते पेड़,धंसते पहाड़,प्रदूषित होती नदियाँ बार बार हमें अपने भविष्य के लिए सचेत करने की कोशिश कर रही है जिन्हें अनसुना कर के हम अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहे है

जलस्रौतों का संरक्षण,उन्हें दूषित होने से बचाना, पौधारोपण, वाटर हार्वेस्टिंग, जैसी बड़ी जरूरतों के साथ हमें पानी बचाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना भी जरूरी है जैसे आरओ फ़िल्टर से बचे वेस्ट पानी का पुनरुपयोग,नहाने के समय वेस्ट होते पानी का पुनरुपयोग, शेव या ब्रश करते समय बेसिन का नल बन्द रखकर मग्गे का उपयोग,टपकते नलों को समय रहते ठीक करवा कर बूंद बूंद पानी बचाकर हम अगली पीढ़ी को अमूल्य उपहार दे पाएंगे ।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने श्रीराम जानकी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की

● श्री रामकथा एवं श्रीराम यज्ञ की तैयारियों का लिया जायजा

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने श्रीराम जानकी मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किये तथा श्री रामकथा एवं श्रीराम यज्ञ की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मडफेश्वर महादेव मंदिर में भगवान आशुतोष के दर्शन किये तथा हवन यज्ञ में आहुति दी। उल्लेखनीय है कि श्रीराम जानकी मंदिर नजरबाग बाबूपुर में 3 जून से 11 जून तक दिव्य श्री रामकथा व श्री रामयज्ञ का आयोजन किया गया है। जगद्गुरू रामानंदचार्य श्री रामललाचार्य जी महाराज की अमृत वाणी से रामकथा का वाचन होगा।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बसामन मामा गौवंश वन्य विहार का किया भ्रमण

● प्राकृतिक खेती का किया अवलोकन, ऋषि कुलम के निर्माण कार्य को गति देने के दिये निर्देश

भोपाल । उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने बसामन मामा गौवंश वन्य विहार का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तदुपरांत श्री शुक्ल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें वन्य विहार में चल रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों को गति देने और व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। भ्रमण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने परिसर में की जा रही प्राकृतिक खेती की गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गौवंश वन्य विहार में व्यवस्थाओं को उच्च स्तरीय बनाया जा रहा है ताकि यह प्राकृतिक खेती और गौसंरक्षण के प्रमुख केन्द्र के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर सके। उन्होंने परिसर में निर्माणाधीन 'ऋषि कुलम' और 'बायो इनपुट सेंटर' का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा निर्देश दिये की सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान एसडीएम दृष्टि जायसवाल, डॉ. राजेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं गौवंश वन्य विहार से संबंधित जन उपस्थित रहे।

भोपाल में 11 परिसरों में बिजली चोरी पकड़ी गई

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल शहर संभाग पूर्व अंतर्गत चांदबढ़ जोन में बिजली चोरी की शिकायतों एवं स्मार्ट मीटरों से प्राप्त संकेतों के आधार पर विशेष जांच अभियान में कार्रवाई की गई। विजिलेंस ऐप में दर्ज मामलों के आधार पर 11 परिसरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। जांच के दौरान कुल 11 परिसरों में विद्युत पोल से सीधे तार जोड़कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए विद्युत चोरी पाई गई। सभी मामलों में नियमानुसार पंचनामा तैयार कर विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। कंपनी ने बताया कि स्मार्ट मीटर एवं डिजिटल निगरानी प्रणालियों के माध्यम से विद्युत चोरी पर लगातार नजर रखी जा रही है। विद्युत चोरी की रोकथाम एवं राजस्व संरक्षण के लिए ऐसे विशेष जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे वैध विद्युत कनेक्शन का उपयोग करें तथा किसी भी प्रकार की विद्युत चोरी या अनियमितता से बचें। विद्युत चोरी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे विद्युत व्यवस्था की गुणवत्ता एवं सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

मुरैना वृत्त में बिजली चोरी के विरुद्ध सघन अभियान, एक दिन में 302 प्रकरण दर्ज

● 50 लाख रुपये से अधिक की राशि की बिलिंग की गई

मुरैना। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना वृत्त में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के विरुद्ध विशेष जांच अभियान के तहत सतर्कता ,ओ एंड एम एवं बीआई सेल की संयुक्त स्थानीय टीमों द्वारा व्यापक जांच कार्रवाई करते हुए कुल 302 प्रकरण दर्ज किए गए। इन सभी मामलों में नियमानुसार आंकलन कर लगभग 50 लाख रुपये से अधिक की राशि की बिलिंग की गई। जांच के दौरान विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत बिजली चोरी के 245 मामलों में पंचनामा तैयार किये गये। वहीं धारा 126 के अंतर्गत 7, धारा 138 के अंतर्गत 17 तथा अन्य 33 प्रकरण दर्ज किए गए। वृत्त के विभिन्न संभागों में सबलगढ़ संभाग में सर्वाधिक 103 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त अंबाह संभाग में 82, मुरैना-1 संभाग में 67 तथा मुरैना-2 संभाग में 50 प्रकरण दर्ज किए गए। कंपनी ने बताया कि बिजली चोरी एवं अनधिकृत विद्युत उपयोग के विरुद्ध यह विशेष अभियान निरंतर जारी रहेगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे वैध विद्युत कनेक्शन का ही उपयोग करें तथा बिजली चोरी जैसी गतिविधियों से दूर रहें। विद्युत चोरी से न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि विद्युत व्यवस्था की गुणवत्ता एवं सुरक्षा भी प्रभावित होती है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी और अनियमितताओं के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा बकाया वसूली एवं राजस्व संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बिजली चोरी के मामले में आरोपी को 2 साल का कारावास और 2.21 लाख रुपये का जुर्माना

मुरैना । मुरैना वृत्त के अंबाह संभाग अंतर्गत विद्युत चोरी के मामले में विशेष न्यायालय (विद्युत) अम्बाह, जिला मुरैना ने आरोपी सरताज खान को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख 21 हजार 176 रुपये की राशि की वसूली के आदेश भी पारित किए हैं। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की सतर्कता टीम द्वारा 12 मई 2016 को अंबाह क्षेत्र में जांच के दौरान आरोपी सरताज खान द्वारा अपनी व्यवसायिक दुकान में अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते हुए बिजली चोरी करते पाए जाने पर मामले में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण क्रमांक 40/2017 में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश विद्युत, मुरैना श्री धीरेंद्र सिंह मंडलोई की अदालत ने दिनांक 03 जून 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी सरताज खान को विद्युत चोरी के अपराध में दोषसिद्ध कर दो वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। न्यायालय द्वारा विद्युत चोरी के सिविल दायित्व के रूप में 2 लाख 21 हजार 176 रुपये की राशि की वसूली के आदेश भी पारित किए गए हैं।

धार वन मंडल की बड़ी पहल

पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाए जा रहे हैं 35 हजार सलाई कटिंग

विश्व पर्यावरण दिवस पर जनभागीदारी से प्रत्येक परिक्षेत्र में रोपे जाएंगे 5-5 हजार पौधे

धार । वनमण्डल अधिकारी, धार वनमण्डल द्वारा वनों के संवर्धन और सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत धार वन मंडल के अंतर्गत आने वाले परिक्षेत्र धार, मांडव, धामनोद, सरदारपुर, कुक्षी, बाग एवं टाण्डा के पुराने तथा नए वृक्षारोपण क्षेत्रों में फेंसिंग के किनारे सलाई की 35,000 कटिंग लगाकर बायो-फेंसिंग का कार्य 1 जून से 7 जून तक किया जा रहा है।

पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से मूल्यवान है सलाई - सलाई पारिस्थितिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण एवं आर्थिक रूप से एक मूल्यवान प्रजाति है। यह राल (शल्लकी/लोबान) का प्रमुख स्रोत है, जिसका औषधीय एवं व्यावसायिक महत्व अत्यधिक है। यह प्रजाति स्थानीय समुदायों को महत्वपूर्ण लघु वनोपज प्रदान करती है तथा शुष्क एवं पथरीले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक स्थापित हो जाती है। जंगलों से लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी इस प्रजाति को पुनर्जीवित करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। सलाई का उपयोग गोंद और माचिस उद्योग के लिए भी किया जाता है।

कम लागत में पौधों को जीवित रखने के लिए अपनाई जा रही है स्टम्प प्लांटिंग पद्धति - वन विभाग द्वारा इस बार रोपण हेतु खूंटा गाड़ पद्धति अपनाई जा रही है। यह वैज्ञानिक पद्धति बेहद कम लागत में पौधों के उच्च जीवित रहने की दर सुनिश्चित करती है। चूंकि सलाई प्रजाति मुश्किल से पनपती है और सामान्यतः 100 में से केवल 20 पौधे ही बच पाते हैं, इसलिए इस तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। कलम से पौधे फूटने और चार-पांच फीट तक बड़े हो जाने के बाद इनका उपयोग प्राकृतिक बायो-फेंसिंग के रूप में होगा, जो सुरक्षा दीवार का काम करेगी।

पौधारोपण में आम लोगों की सहभागिता भी रहेगी - इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक परिक्षेत्र में 5000 सलाई कटिंग का रोपण जनप्रतिनिधियों, आमजन और वन समितियों की सक्रिय सहभागिता के साथ मिलकर सांकेतिक पौधा रोपण कार्यक्रम के रूप में किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, 2 खाद्य कारोबारियों के बिना लाइसेंस व्यापार करने पर बने प्रकरण, 6 प्रतिष्ठानों से जांच हेतु लिए 13 नमूने

सभी नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए

धार। कलेक्टर राजीव रंजन मीना के निर्देशानुसार एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्य प्रदेश के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला धार द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान दो प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के व्यापार करते पाए गए, जिन पर नियमानुसार प्रकरण तैयार किए गए हैं। 6 प्रतिष्ठानों से कुल 13 नमूने जांच हेतु लिए गए हैं।

बिना लाइसेंस व्यापार पर कार्यवाही और 27 टन चावल जब्त - खाद्य सुरक्षा दल द्वारा ग्राम रेशमगारा, तहसील बदनावर स्थित नानेश किराना का निरीक्षण किया गया। यहाँ विक्रेता गिरधारीलाल पिता नानूराम पाटीदार बिना लाइसेंस के व्यापार करते पाए गए। मौके पर नानेश किराना का बिना लाइसेंस का प्रकरण बनाकर जांच हेतु निधि ब्रांड मिर्च पाउडर एवं बसंत ब्रांड हल्दी पाउडर के नमूने लिए गए। इसी प्रकार अणु नगर, उन्नति स्कूल के पीछे, बदनावर स्थित महावीर ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया। यहाँ उपस्थित प्रभारी विक्रेता सौरभ पिता रमेश चंद जैन के पास खाद्य लाइसेंस न होने पर बिना लाइसेंस के व्यापार का प्रकरण बनाया गया। मौके पर परिसर में खड़े दो वाहनों में मौजूद चावल में से दो नमूने जांच हेतु लिए गए तथा 27 टन चावल जब्त कर विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा गया। इसके अतिरिक्त अणु नगर बदनावर स्थित विजय ट्रेडर्स से स्प्राइट लेमन एंड मिंट कोल्ड ड्रिंक का नमूना जांच हेतु लिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मनावर क्षेत्र में भी सघन निरीक्षण किया गया, लिए गए नमूने - बालाजी बेकरी एंड कैफे (मनावर) से लाल गुलाब सुपरफाइन मैदा, पूरी बेकिंग पाउडर, खत्रीजी कॉन्टिनेंटल सॉस और चॉकलेट केक के नमूने लिए

गए। जयमाताजी जूस सेंटर (इंदौर रोड, मनावर) से आम रस और लस्सी के नमूने लिए गए। खंडेलवाल बेकरी हाउस (सिंघाना रोड, मनावर) से ब्रेड और मैदा के नमूने जांच हेतु लिए गए।

भोपाल भेजी गई रिपोर्ट, होगी सख्त कार्यवाही - कार्यवाही के दौरान लिए गए सभी 13 नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेज दिया गया है। अभिहित अधिकारी ने बताया कि प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधितों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आगामी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस संपूर्ण कार्यवाही में अभिहित अधिकारी सचिन लौंगरिया, आर. जी. माउता एवं सुभाष खेडकर सक्रिय रूप से शामिल रहे।

चंचल कहार को मिला 25 हजार का फोन, जाहिर की खुशी, आपरेशन माई फोन से 5 लाख के मोबाइल मिले वापस

सोहागपुर । श्रीमान पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री साईकृष्णा एस. थोटा,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक राजन नर्मदापुरम एवं एसडीओ पुलिस श्री संजू चौहान सोहागपुर ने गुम हुए मोबाइलों धारकों को राहत पहुंचाने को लेकर गंभीरतापूर्वक नगर निरीक्षक राहुल रायकवार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उल्लेखनीय है कि शभारत सरकार के द्वारा सीईआईआर पोर्टल संचालित किया गया है।इस अत्याधुनिक तकनीक एक केंद्रीकृत प्रणाली है । इस तकनीक, पोर्टल के माध्यम से कोई गुम एवं चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने एवं ब्लॉक करने में मदद मिलती है। इसी तकनीक से थाना सोहागपुर में पिछले 05 माह में थाना में 41 शिकायतें प्राप्त हुई थी।जिनमें 25 मोबाइल मोबाइल धारकों को वापस किए गए ।जिसकी कीमती

लगभग 5लाख रुपये है। पुलिस ने शेष बचे गुम हुए मोबाइल भी ढूंढ कर शिकायतकर्ताओं को शीघ्र वापस कराये जाएगें।इसी श्रृंखला में वनप्लस कंपनी का एक मोबाइल जिसकी कीमती 25 हजार रुपए का शिकायतकर्ता चंचल कहार पति डालचंद कहार निवासी मातापुरा सोहागपुर वापिस किया गया। इससे शिकायकर्ता काफी प्रसन्न हुई। ज्ञातव्य है कि विगत दिवस मंगलवार को जमनी सरोवर हनुमान धाम मंदिर में दर्शन के लिए गई थी । इसी बीच उनका मोबाइल गुम हो गया था । उक्त प्रणाली के माध्यम से ढूंढकर आज वापस किया गया है। पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी अथवा गुम होता है तो थाने में शिकायत जरूर करें।

ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 'आरोह 2026' का भव्य समापन, प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए

सोहागपुर । संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग, भोपाल के आदेशानुसार जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सुश्री उमा पटेल के निर्देशन में आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का आज पंडित जवाहरलाल नेहरू खेल मैदान, सोहागपुर पर भव्य समापन हुआ। उक्त कार्यक्रम डॉक्टर अरविंद चौहान खेल अकादमी, शिक्षा विभाग एवं खेल युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर ब्लॉक खेल समन्वयक श्रीमती चंदा मिश्रा ने कहा कि 1 मई से 31 मई तक चले इस समर कैंप में 'खेलो सीखो आगे बढ़ो' थीम पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके मुख्य घटक फिट इंडिया मूवमेंट, व्यक्तिगत विकास, संस्कृति एवं मनोरंजन, खेल गतिविधियां, फैमिली इंगेजमेंट, सोसाइटी इंगेजमेंट एवं सामाजिक जागरूकता रहे। शिविर में बच्चों ने फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी एवं कराटे खेलों की बारीकियां सीखीं। इस गरिमामय कार्यक्रम में समाजसेवी कन्नू लाल अग्रवाल, हमीर सिंह चंदेल,आकाश रघुवंशी, अश्विनी सरोज, नगर पालिका अधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा सहायक संचालक शिक्षा विभाग राकेश उइके, योग शिक्षक श्री जितेंद्र बैरागी उपस्थित रहे। समस्त खेलों के पीटीआई एवं प्रशिक्षक उपस्थित थे। इस

गरिमामय कार्यक्रम में समस्त समर कैंप में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को मेडल, ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र अतिथियों ने प्रतिभागियों को प्रदान किए।

इसी अवसर पर अतिथियों ने सारगर्भित उद्बोधन देकर प्रतिभागियों का हौसला अफजाई की।कार्यक्रम का संचालन योग शिक्षक श्री जितेंद्र बैरागी ने किया । उक्त आश्य की जानकारी आशु राय ने इस प्रतिनिधि को दी।

5 से 21 जून तक चलेंगे जन उत्सव कार्यक्रम, घर-घर पहुंचाई जाएंगी भाजपा सरकार की उपलब्धियां

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

धार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को केंद्रीय राज्यमंत्री क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती संगठन जिला प्रभारी सुभाष कोठारी, धार विधायक नीना वर्मा ने संबोधित किया। कार्यशाला का शुभारंभ भारत माता , पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पूजन के साथ किया गया। जिलाध्यक्ष निलेश भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 सफल वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में भारत ने विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं तथा समाज के प्रत्येक वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उन्होंने बताया कि 5 जून से 21 जून तक ÷जन उत्सव÷ अभियान के तहत जिलेभर में विभिन्न संगठनात्मक एवं जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव एवं घर-घर पहुंचकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगे।

केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष ऐतिहासिक निर्णयों और जनकल्याणकारी कार्यों के लिए याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के हर वर्ग के विकास के साथ शासन व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।

सावित्री ठाकुर ने कहा कि धार जिले में रेल परियोजना का सपना भाजपा सरकार साकार कर रही है, जिससे क्षेत्र के विकास को

नई गति मिलेगी। उन्होंने बदनावर में देश के पहले पीएम मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भोजशाला में प्रस्तावित माँ सरस्वती लोक निर्माण को संस्कृति, आस्था और सभ्यता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

जिला प्रभारी सुभाष कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12 वर्षों तक देश का नेतृत्व करते हुए भारत की ताकत और प्रतिष्ठा को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना एवं मुफ्त राशन जैसी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री राजवर्धनसिंह दत्तीगांव, पूर्व विधायक वेलसिंह भूरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु राठौड़ एवं दिलीप पटोंदिया, जिला महामंत्री देवेंद्र सोनोने व राकेश पटेल अभियान जिला टोली से कपिल निनामा ,डॉ अमृत पाटीदार, रोमा मंडलोई, रितेश अग्निहोत्री, पियूष सोनगरे विशेष रूप से उपस्थित रहे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया गया कि ÷12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के÷ अभियान के अंतर्गत 5 जून से 21 जून तक जिलेभर में वृक्षारोपण, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, प्रदर्शनी, मीडिया संवाद, विशेष जनसंपर्क अभियान एवं विभिन्न जनजागरण कार्यक्रम तथा जन कल्याण शिविर प्रबुद्धजन सम्मेलन प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजित किए जाएंगे। कार्यशाला का संचालन पीयूष सोनगरा ने किया तथा आभार भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं टोली संयोजक कपिल निनामा ने माना।

कलेक्टर के निर्देशानुसार बरसात के पूर्व नगर के नालों, नालियों का सफाई अभियान प्रारंभ

सोहागपुर । कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर पंचायत परिषद ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान प्रारंभ कर दिया है। इसी तारतम्य में मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन वर्षा पूर्व नाला सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में नाला सफाई अभियान के तहत मातापुरा क्षेत्र में विशेष सफाई कार्य नगर पंचायत परिषद ने वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए चलाए जा रहे हैं जिसमें नाला-नाली सफाई अभियान के अंतर्गत मातापुरा वार्ड में विभिन्न स्थानों पर जेसीबी के माध्यम से व्यापक सफाई कार्य किया गया। इसी क्रम में मुन्ना चक्की के पास, मातापुरा स्कूल के समीप एवं बड़ी मस्जिद के पास स्थित नालों की सफाई करके नालियों में जमा गाद एवं मलवे निकाल कर निर्धारित गन्तव्य स्थानों पर

ट्रेक्टर ट्रॉली के माध्यम से भिजवाया गया । शास्त्री वार्ड के पास - विश्राम गृह के पास वाले नाले की विशेष सफाई कर जमा मलवे को निकालकर क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल, पार्षद श्री गौरव पालीवाल, पार्षद भास्कर मांझी , नगर पंचायत परिषद उप स्वच्छता निरीक्षक अमित परसाई आदि उपस्थित थे।।मुख्य नगर परिषद अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि वर्षा ऋतु में जलभराव की समस्या से नागरिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नगर के सभी वार्डों के प्रमुख नालों एवं नालियों की चरणबद्ध तरीके से सफाई की जा रही है। आपने नागरिकों से भी अपील की है।कि आमजन कचरे को नाले, नालियों में न डालें । इसके साथ ही आपने कहा कि सोहागपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है

विद्युत उपभोक्ता विद्युत व्यवधानों से मुक्ति पाएं,स्वैच्छिक भार (लोड) वृद्धि स्वीकृत करवायें

भोपाल । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने परिसर के वास्तविक विद्युत भार के अनुरूप अपने कनेक्शन की भार वृद्धि स्वेच्छा से स्वीकृत कराना सुनिश्चित करा लें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत भार की वृद्धि स्वेच्छा से कराने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने का अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है। कंपनी ने बताया है कि उपभोक्ता कंपनी के पोर्टल पर स्वैच्छिक ऑनलाइन आवेदन कर भार वृद्धि करा सकते हैं।

गौरतलब है कि है कि विद्युत उपभोक्ता कंपनी द्वारा स्वीकृत विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग करते हैं जिससे कम्पनी की विद्युत अधोसंरचना अतिभारित हो जाती है जो कि अनावश्यक रूप से विद्युत व्यवधानों का कारण बनती है। अतः सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे स्वेच्छा से अपने विद्युत भार की वृद्धि करा लें जिससे कम्पनी द्वारा भार अनुरूप उपयुक्त विद्युत अधोसंरचना का विकास कर बेहतर एवं निर्बाध विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके।

श्रीराम कथा भवसागर से पार उतारती है - उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल

● जगद्गुरू श्री रामललाचार्य जी से उप मुख्यमंत्री ने लिया आशीर्वाद ● श्रीराम कथा एवं श्रीराम महायज्ञ का हुआ शुभारंभ

भोपाल । उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि श्रीराम कथा भवसागर से पार उतारती है। एक राम नाम ही इस शरीर रूपी रथ का संवाहक है। ऐसे अवसर बड़े मनोरथों के उपरांत आते हैं इसलिए हम सब अपने मनोरथ को पूर्ण करें। श्री शुक्ल श्रीराम कथा एवं श्रीराम महायज्ञ के शुभारंभ अवसर पर शामिल हुए। उन्होंने जगद्गुरू श्री रामललाचार्य जी से आशीर्वाद लिया।

श्रीराम जानकी मंदिर नजरबाग बाबूपुर में आयोजित श्रीराम कथा में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जगद्गुरू की अमृत वाणी से रामकथा का रसास्वादन 9 दिनों तक होगा और जनमानस कृतार्थ होगा तथा श्रीराम के चरित्र को अपने ह्मदय में बसायेगा। उन्होंने कहा कि श्रीराम एवं श्रीकृष्ण की कथा ज्ञान की गंगा है और जब वह महाराज जी जैसे ऋषियों की अमृत वाणी से कही जायेगी तो और भी ज्ञानप्रद होगी। उन्होंने कहा कि महाराज जी का आगमन सौभाग्य की बात है। यह स्थल तीर्थ बनेगा। आज कथा का प्रथम दिवस है और भक्तजनों में अपार उत्साह है। मंदिर में होने वाली रामकथा का सौ गुना लाभ मिलता है। श्री शुक्ल ने कहा कि ईश्वर की कृपा और गौमाता के आशीर्वाद से ही रीवा का विकास हुआ है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही होता है। उन्होंने कहा कि भगवान भक्त से प्रसन्न होते हैं और शरणागत को ही भक्त मानते हैं।

प्रथम दिवस की कथा में जगद्गुरू ने श्रीराम के चरित्र का गुणगान करते हुए कहा कि श्रीराम हमारे रोम-रोम में बसते हैं। उनके द्वारा स्थापित आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। राम का चरित्र सर्वश्रेष्ठ है और इतिहास में रामायण सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। विन्ध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पंचूलाल प्रजापति, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र गुप्ता, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में भक्तजनों ने प्रथम दिवस की कथा का श्रवण किया।

गतदिवस निकाली गई कलश यात्रा - रामकथा से पूर्व गतदिवस कलश यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। बीटीएल बाला जी मंदिर से आरंभ होकर कलश यात्रा भुंइया बाबा की पूजा-अर्जना के उपरांत श्रीराम जानकी मंदिर में संपन्न हुई। इस दौरान जगद्गुरू का भक्तजनों ने स्वागत एवं वंदन किया।

कार्यालय तहसीलदार प्रभातपट्टन, जिला बैतूल

रा.प्र.क्र.00382/अ/6 वर्ष 2025-26 मौजा- चिचण्डा

1. हरप्रीत खुराना पिता आजादसिंह खुराना,
निवासी विवेकानंद वार्ड मेन रोड मुलताई, जिला बैतूल

// बनाम //

1. चैती पति रामा
2. सुखिया पति दिन्या
3. कौशल बेवा पन्ना
4. झनक पिता पन्ना
5. गुलाब पिता पन्ना
6. माया पिता पन्ना
7. प्रमिला पिता पन्ना
8. महादेव पिता गोपाल
9. पुसलीबाई पति महादेव
10. द्रोपती पति कालूराम

// सूचना पत्र //

आपको सूचित किया जाता है कि आवेदिका हरप्रीत खुराना पिता आजादसिंह खुराना निवासी विवेकानंद वार्ड, मुलताई, जिला बैतूल द्वारा मौजा चिचण्डा की भूमि खसरा नंबर 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/12, 63/13 रकबा क्रमशः 0.247, 0.210, 0.650, 0.375, 0.510, 0.804, 0.860, 0.120, 0.110, 0.110, 0.070, 0.215, 0.110 है. भूमि का उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 412/81 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21/03/1987 के अनुसार मौजा चिचण्डा की भूमि का नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में इस न्यायालय में दिनांक 05/06/2026 को उपस्थित होकर मय दस्तावेजों आप स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते है। अनुपस्थित की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

सील तहसीलदार, प्रभातपट्टन

9 लाख की लूट का खुलासा, 5 आरोपी

मास्टरमाइंड अब भी फरार, 10 हजार का इनाम घोषित

बैतूल। बैतूल पुलिस ने बोरदेही थाना क्षेत्र में 20 मई को हुई 9 लाख रुपये की लूट का खुलासा किया है। इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता अभी भी फरार है। पुलिस अधीक्षक ने फरार आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने आरोपियों से नगद राशि, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और लूट के पैसों से खरीदी गई दो अन्य मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार, आईसीआईसीआई बैंक आमला से 9 लाख रुपये निकालकर बोरदेही लौट रहे प्रदीप झरबड़े को आरोपियों ने पहले से ही निशाना बनाया था। 20 मई को ग्राम नरेरा और देहलवाड़ा के बीच एक सुनसान रास्ते पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनका पीछा किया। आरोपियों ने प्रदीप झरबड़े की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका, जिससे वह मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिर गए। इसके बाद चाकू की नोक पर रुपयों से भरा बैग लूटकर आरोपी फरार हो गए। इस घटना में फरियादी को हल्की चोटें भी आई थीं। घटना के बाद बोरदेही थाने में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में रामकुमार उर्फ मोहित यदुवंशी (18), गोविंद टांडेकर (19), शिवराम उर्फ नान्हू बन (20), दुर्गेश सोनवंशी (22) और कमलेश उर्फ मनीष यदुवंशी (26) शामिल हैं। ये सभी आरोपी छिंदवाड़ा जिले के नवेगांव और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से 60 हजार रुपये नकद, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और लूट की रकम से खरीदी गई दो अन्य मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। पुलिस शेष रकम की बरामदगी के प्रयास कर रही है।

मास्टरमाइंड अभी भी फरार, गिरफ्तारी पर इनाम – इस गिरोह का मास्टरमाइंड देवानंद उर्फ देवा इवने निवासी घाना उमरी, थाना नवेगांव, जिला छिंदवाड़ा अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। फरार आरोपी देवानंद के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, चोरी, नकबजनी, लूट और जुआ एक्ट सहित आधा दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वह थाना नवेगांव का निगरानी बदमाश भी है। पुलिस का मानना है कि उसी ने पूरी वारदात की योजना बनाई थी। मामले के खुलासे में थाना बोरदेही, थाना आमला, थाना नवेगांव, थाना जुन्नारदेव और साइबर सेल की संयुक्त टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

विश्व साइकिल दिवस पर मेरा युवा भारत बैतूल द्वारा साइकिल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बैतूल । मेरा युवा भारत बैतूल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री हंसराज धुर्वे, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला खेल अधिकारी श्रीमती पूजा कुरिल उपस्थित रहीं। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने युवाओं को नियमित रूप से साइकिल चलाने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि साइकिल न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि प्रदूषण कम करने एवं ईंधन की बचत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिला युवा अधिकारी मेरा युवा भारत बैतूल सुषमा गवली ने बताया कि विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य साइकिलिंग को स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास से जोड़कर बढ़ावा देना है।

अमरदीप की मौत के बाद अनमोल अस्पताल के विरुद्ध सडक़ों पर फुटा गुस्सा

बढ़ा आक्रोश, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, युवाओं का प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

बैतूल/मुलताई। नगर के निजी अस्पताल अनमोल हॉस्पिटल में उपचार के बाद युवा व्यवसायी अमरदीप सिंह (सन्नी) की 27 मई को हुई मृत्यु के मामले को लेकर नगर में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को बड़ी संख्या में युवाओं ने साईं सेवा समिति एवं हनुमान सेवा समिति के बैनर तले विरोध रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अस्पताल संचालक डॉ. प्रवीण शुक्ला पर चिकित्सा सेवाओं में कथित लापरवाही बरतने तथा स्वास्थ्य संबंधी मानकों की अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मुलताई स्थित अनमोल अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नगरवासियों एवं मरीजों के परिजनों के बीच लंबे समय से असंतोष एवं गंभीर शिकायतें सामने आती रही हैं। ज्ञापनकर्ताओं का आरोप है कि अस्पताल में उपचार संबंधी लापरवाही, चिकित्सा मानकों की अनदेखी तथा विभिन्न नियमों के उल्लंघन के संबंध में समय-समय पर शिकायतें की जाती रही हैं, लेकिन अब तक प्रभावी जांच और कार्रवाई नहीं होने से आमजन में रोष बढ़ा है।

अमरदीप और मोहित पाल प्रकरण का उल्लेख – ज्ञापन में हाल ही में अस्पताल में उपचाररत रहे युवा अमरदीप सिंह (सन्नी) की मृत्यु का उल्लेख करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। साथ ही लगभग एक वर्ष पूर्व नगर के युवक मोहित पाल की मृत्यु के मामले में भी उपचार संबंधी गंभीर प्रश्न उठाए गए थे। ज्ञापनकर्ताओं का कहना है कि इन घटनाओं सहित अन्य मामलों में भी अस्पताल के विरुद्ध उपचार संबंधी शिकायतें सामने आती रही हैं, जिन्हें गंभीरता से जांचा जाना आवश्यक है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई मामलों में मरीजों की वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति का समुचित परीक्षण किए बिना उपचार किया जाता है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार कई बार उपचार के बाद मरीजों की स्थिति में सुधार होने के बजाय और अधिक गंभीरता आ जाती है।

पैथोलॉजी जांच में अनियमितता, चिकित्सा मानकों के पालन पर सवाल – ज्ञापन में अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में योग्य एवं प्रमाणित लैब टेक्नीशियन की उपलब्धता पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया एवं विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के अभाव में जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिससे मरीजों के उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञापनकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मरीजों को दी जाने वाली दवाओं एवं उपचार संबंधी दस्तावेजों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं मानकों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि अनेक मरीजों को दिए गए प्रिस्क्रिप्शन पर चिकित्सक के स्पष्ट हस्ताक्षर, पंजीयन क्रमांक अथवा अन्य आवश्यक विवरण अंकित नहीं पाए गए, जो चिकित्सा आचार संहिता के विपरीत है। अस्पताल परिसर अथवा उससे संबंधित मेडिकल स्टोर से निम्न गुणवत्ता की दवाएं उपलब्ध कराए जाने के आरोप भी ज्ञापन में लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने इसकी भी जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं है तथा कई संवेदनशील चिकित्सकीय कार्य अप्रशिक्षित कर्मचारियों से कराए जाते हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ज्ञापनकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि मरीजों के जीवन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गडेकर, चिंटू खन्ना, सुमित शिवहरे, निखिल जैन, आकाश राजपूत, राहुल वराठे, कुलदीप भावसार, लकी मस्तकार, दीपक सोलंकी, हेमंत मस्की, जय सूर्यवंशी, नितेश रावत, नितेश शर्मा, सौरभ शर्मा सहित बड़ी संख्या में युवा एवं नागरिक उपस्थित रहे।

इनका कहना है – मैंने इलाज में कोई गलती नहीं की, मेरे यहां जो मरीज का इलाज किया गया, उनका बीपी लो था, इलाज करके घर भेज दिया था। उसके बाद कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं कोई एमडी मेडिसिन नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल फिजिशियन हूं। आप कैसे उम्मीद कर सकते कि मैं हार्ट का भी इलाज करूंगा।

-डॉ. प्रवीण शुक्ला, संचालक, अनमोल हॉस्पिटल मुलताई

पौधरोपण के साथ पौधों का संरक्षण भी सुनिश्चित करें : कलेक्टर

- **पौधरोपण स्थलों पर फेंसिंग और रखरखाव किए जाने के दिए निर्देश**
- **कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने की एक पेड़ मां के नाम अभियान, जनकल्याणकारी शिविर और योग कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा**

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान, जनकल्याणकारी शिविर, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन तथा सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 5 जून को जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका को स्पाट का चयन किए जाने के निर्देश दिए, जहां बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में डेवलप किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने वन विभाग, जन अभियान परिषद को स्थान चयन कर वृहद स्तर पर पौधरोपण की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने जन अभियान परिषद को भी निर्देशित किया कि दो पहाडयिों का चयन किया जाए, जहां पौधरोपण कर उन्हें वृक्षों से आच्छादित किया जा सके। उन्होंने पौधरोपण के संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पौधों के रखरखाव का विशेष ध्यान रखे। इसके अलावा उन्होंने पौधरोपण किए गए स्थानों पर अनिवार्य रूप से फेंसिंग कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने साफ-सफाई अभियान की समीक्षा के दौरान माचना नदी पर विशेष साफ-सफाई अभियान आयोजित किए जाने और जल स्त्रोतों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर साफ सफाई और परियोजना नगर पालिका अधिकारी को शहरी क्षेत्र में साफ सफाई अभियान सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय में पानी और साफ सफाई सुनिश्चित कर उन्हें क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पौधरोपण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को वृहद स्तर पर पौधरोपण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर पौधरोपण के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कार्यालय में विशेष साफ सफाई अभियान चलाकर अभिलेखों का व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

शिविरों के आयोजनों के दिये निर्देश – जनकल्याणकारी शिविर का आयोजन कर पीएम स्वनिधि, आयुष्मान, पीएम सूर्य घर बिजली योजना, सहित अन्य योजनाओं में सेचुरेशन लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनकल्याणकारी शिविर के आयोजन के लिए एसडीएम एवं सहायक नोडल के रूप में जनपद सीईओ, नगर पालिका सीएमओ रहेगे। इसके अलावा उन्होंने सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी की शिकायतों का भी गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों एवं पर्यटन स्थलों पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी स्थान चिन्हित कर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्व सहायता समूह की महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर वंदना जाट, एसडीओ फॉरेस्ट सुंदर निवेदन, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत इंदिरा महतो, सीएमओ नवनीत पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें।

अधिराज ने जेईई एडवांस में हासिल की 234वीं रैंक

बैतूल। पटेल वार्ड सदर बैतूल निवासी डॉ. लोकेश अग्रवाल एवं डॉ. श्वेता अग्रवाल के सुपुत्र तथा वीरेन्द्र सिंह चौहान एवं श्रीमती साधना चौहान के पौत्र अधिराज अग्रवाल ने देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर परिवार, नगर एवं जिले का नाम गौरवान्वित किया है। अधिराज ने जेईई एडवांस्ड (आईआईटी प्रवेश परीक्षा) 2026 में ऑल इंडिया रैंक 234 प्राप्त कर सफलता अर्जित की है। इसके पूर्व उन्होंने जेईई मेन्स 2026 में 99.95 परसेंटाइल हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। इसके अलावा अधिराज ने कॉमेडके 2026 परीक्षा में भी ऑल इंडिया रैंक 59 प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। उनकी इस सफलता से परिवार, मित्रों, शिक्षकों एवं शुभचिंतकों में हर्ष का माहौल है।

जनसुनवाई में पहुंचा सीमांकन का मामला

- **शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग**

आमला। सीमांकन प्रक्रिया के दौरान वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया है। इसकी शिकायत जनसुनवाई में की है। वयोवृद्ध आधार सिंह सोलंकी द्वारा जनसुनवाई में प्रस्तुत शिकायत में 01 अप्रैल 2024 को तैयार किए गए सीमांकन प्रतिवेदन को नियम-विरुद्ध एवं तथ्यों से परे बताते हुए उसे निरस्त करने, कथित अवैध अतिक्रमण हटाने तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सीमांकन प्रक्रिया के दौरान वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। सीमांकन से पूर्व आवश्यक नोटिस की तामील, संबंधित पक्षों की सुनवाई, राजस्व अभिलेखों का समुचित परीक्षण तथा कारणयुक्त आदेश जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं की उपेक्षा की गई। मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उस मार्ग से जुड़ा है, जिसका स्पष्ट उल्लेख शिकायतकर्ता के पंजीकृत विक्रय पत्र में दर्ज होने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त मार्ग पर निर्माण कार्य कर आवागमन का अधिकार बाधित किया जा रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि सीमांकन प्रतिवेदन में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया तथा प्रक्रिया में अपेक्षित पारदर्शिता नहीं बरती गई। सीमांकन शुल्क, पंचनामा, मौके की वास्तविक स्थिति तथा अभिलेखीय परीक्षण से जुड़े अनेक बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। जनसुनवाई में दिए गए आवेदन में सीमांकन प्रतिवेदन को तत्काल निरस्त कर स्वतंत्र अधिकारी की निगरानी में पुन- सीमांकन कराने, अवरुद्ध मार्ग को खुलवाने, कथित अतिक्रमण हटाने तथा मामले से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

हड़ताल के दूसरे दिन संविदा कर्मचारियों ने दिखाई सेवा भावना, राहगीरों को बांटा ओआरएस

- **निष्कासन आदेशों के विरोध में फूटा कर्मचारियों का गुस्सा, की सद्बुद्धि प्रार्थना**
- **एनएचएम कर्मचारियों के आंदोलन को मिला संगठनों का समर्थन**

बैतूल। नियमितीकरण सहित आठ सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के दूसरे दिन 3 जून को कर्मचारियों ने जहां अपनी मांगों को लेकर शासन और विभागीय अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की, वहीं सामाजिक दायित्व निभाते हुए भीषण गर्मी के बीच राहगीरों के लिए ओआरएस घोल एवं जलपान की व्यवस्था कर जनसेवा का संदेश दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े होने के नाते संघर्ष के बीच भी आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। धरना स्थल पर मौजूद संविदा कर्मचारियों ने गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राहगीरों, आम नागरिकों और आसपास से गुजरने वाले लोगों को ओआरएस घोल का वितरण किया। कर्मचारियों ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी होने के नाते समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी कार्यस्थल तक सीमित नहीं है। आंदोलन के दौरान भी जनहित और जनस्वास्थ्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कायम है। इस पहल को लोगों ने भी सराहा और कर्मचारियों की सेवा भावना की प्रशंसा की।

अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए की प्रार्थना – आंदोलन के दौरान कर्मचारियों ने एनएचएम प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए निष्कासन संबंधी आदेशों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने इन आदेशों को तानाशाहीपूर्ण बताते हुए कहा कि वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के बजाय दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। विरोध स्वरूप कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की और शांतिपूर्ण तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त किया। कर्मचारियों का कहना है कि मांगों के समाधान के स्थान पर दबाव बनाने की कोशिशें आंदोलन को और मजबूत करने का काम करेंगी।

मांगों के समर्थन में उतरे श्रमिक और शिक्षक संगठन – आंदोलन को विभिन्न कर्मचारी संगठनों का समर्थन भी मिलने लगा है। धरना स्थल पर भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री पंजाब गायकवाड़ एवं शिक्षक संघ के नरेश लहरपुरे पहुंचे। दोनों ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उनकी मांगों को न्यायोचित बताया और संघर्ष में पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए तथा सरकार को इस दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

मांगों के निराकरण तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान – संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण, एनपीएस, स्वास्थ्य बीमा, वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति दूर करने सहित अन्य मांगों के निराकरण तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से शासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी कारण प्रदेशव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।

जल संरक्षण के लिए रिचार्ज स्ट्रक्चर के काम तेजी से पूर्ण कराएं : कलेक्टर डॉ सोनवणे

- **आंगनबाड़ी में भोजन और नाश्ता नहीं मिलने की शिकायत पर सीडीपीओ, सुपरवाइजर को नोटिस और समूह को हटाने के निर्देश**
- **कलेक्टर ने ग्राम कुनखेड़ी में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं**

बैतूल । कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे ने बुधवार को भीमपुर विकासखंड के ग्राम कुनखेड़ी का निरीक्षण कर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया तथा विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से जल संरक्षण, शिक्षा, बिजली, सड़क, आंगनवाड़ी एवं आजीविका गतिविधियों की समीक्षा की। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में वाटर लेवल नीचे जाने से पेयजल समस्या उत्पन्न हो रही है, वहां अनिवार्य रूप से जल संरक्षण के लिए रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएं। उन्होंने जनपद के इंजीनियरों को निर्देशित किया कि 20 जून तक सभी कार्य पूर्ण सुनिश्चित किए जाएं। ग्रामीणों ने ग्राम पालगा, उतरी एवं बतोडी में बिजली समस्या से अवगत कराया। इस पर कलेक्टर डॉ सोनवणे ने बताया कि तीनों ग्रामों में बिजली आपूर्ति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है तथा स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य तेजी से पूर्ण कर बिजली व्यवस्था सुचारू की जाएगी। उन्होंने ग्राम बतोडी की सड़क समस्या का भी शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश दिए।

100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम और कैरियर काउंसलिंग के निर्देश – ग्राम कुनखेड़ी में हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं होने से विद्यार्थियों को दूर जाना पड़ता है। इस पर कलेक्टर डॉ सोनवणे ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को वर्तमान स्कूल के उन्नयन का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों की कमी से प्रभावित परीक्षा परिणामों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्राथमिकता से शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्मार्ट क्लास के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की स्वयं मॉनिटरिंग करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने एवं 12वीं के बाद विद्यार्थियों को उनकी रुचि अनुसार कैरियर काउंसलिंग उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

कुनखेड़ी सोसाइटी क्रियाशील करने के निर्देश – ग्रामीणों द्वारा कुनखेड़ी स्वीकृत सोसायटी में खाद आवंटन नहीं होने की समस्या उठाई गई, जिस पर कलेक्टर डॉ सोनवणे ने अधिकारियों को शीघ्र समाधान कर सोसाइटी को क्रियाशील करने के निर्देश दिए। ग्राम चोहटापट्टी में आंगनबाड़ी एवं सोसाइटी की बाउंड्रीवाल निर्माण के निर्देश पंचायत को दिए गए।

नाश्ता एवं भोजन नहीं मिलने पर कलेक्टर सख्त – आंगनबाड़ी में बच्चों को 5 जून से पहले कुछ दिनों तक नाश्ता एवं भोजन नहीं मिलने की शिकायत पर कलेक्टर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सुपरवाइजर से जानकारी ली। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित समूह को तत्काल हटाने तथा सुपरवाइजर एवं सीडीपीओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी शिकायत मिलने पर सीडीपीओ की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एनआरएलएम समूह को मध्यान्ह भोजन संचालन की जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए।

आजीविका गतिविधियों को बढ़ाने और मार्केट लिंकेज के निर्देश – कलेक्टर डॉ सोनवणे ने चौपाल में समूह की महिलाओं की गतिविधियों के संचालन के लिए प्राथमिक शाला में भवन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं को मुर्गी पालन, मल्टी लेयर यूनिट, सिलाई जैसी आजीविका गतिविधियों से जोड़ने एवं मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

कालिया सुखराम के ई केवाईसी कर राशन वितरण कराएं – इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीणों की व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन, अतिक्रमण, रास्ता विवाद एवं चौपाल निर्माण जैसी समस्याओं पर सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। राशन वितरण की समीक्षा के दौरान आवेदक कालिया सुखराम की ई-केवाईसी नहीं होने से राशन नहीं मिलने की शिकायत पर तत्काल ई-केवाईसी कर राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से राशन वितरण, पटवारी की उपस्थिति एवं अन्य शासकीय व्यवस्थाओं की जानकारी भी प्राप्त की। इस दौरान एसडीएम श्री अजीत मरावी, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत श्रीमती इंदिरा महतो, जनपद सीईओ भीमपुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मेंटेनेंस आज, बंद रहेगी बिजली

बैतूल। बिजली कंपनी द्वारा एसएसटीडी योजना के अंतर्गत 33/11 केवी हमलापुर उपकेंद्र पर 4 जून को मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। मेंटेनेंस कार्य के चलते गुरुवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हमलापुर उपकेंद्र के समस्त 11 केवी फीडर पर विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल शहर जोन- 1 के प्रबंधक ने बताया कि प्रस्तावित कार्य के चलते खंजनपुर क्षेत्र के दुर्गा वार्ड, कत्तलढाना, डिपो रोड, विकास नगर, गोयल फैक्ट्री, माचना नगर, अर्जुन वार्ड तथा कालापाठा के लोहिया वार्ड, चुन्नीढाना, राजेन्द्र वार्ड, सिविल लाईन, सजंय कॉलोनी, मुर्गी चौक, शिवाजी वार्ड, स्वीपर कॉलोनी जेएच कॉलेज रोड और गंज क्षेत्र के आबकारी, सिन्धी कालोनी, देना बैंक, लोहिया वार्ड, तेल टंकी, लक्की सेंटर, कांतिशिवा टाकीज, सेन्ट्रल बैंक, एसबीआई बैंक, मैकेनिक चौक, अग्रवाल पेट्रोल पम्प, बीजेपी कार्यालय, डॉ.मुले गुरूद्वारा रोड, हाथी नाला, डॉ. लश्करे, बीएसएनएल ऑफिस पुलिस क्वार्टर हाउसिंग बोर्ड गंज महाराष्ट्र बैंक, ग्रीन सिटी के विनोबा नगर, विवकांनद वार्ड, भग्गूढाना, खादी उद्योग के पास, ग्रीन सीटी, माचना नगर, हमलापुर चौक, फारेस्ट ट्रेनिंग सेन्टर, जजेस कॉलोनी आदि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग

मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समय-सीमा में पूरा करें- सचिव

भोपाल (नप्र)। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समय-सीमा में पूरा करें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दीपक सिंह ने यह बात पंचायत एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान

कही। श्री सिंह ने जिलेवार लंबित दावे-आपत्तियों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्य में पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में जो भी कार्यवाही करें, उसकी जानकारी स्टेरिंग कमेटी की बैठक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में जरूर लायें। उन्होंने वर्किंग और नानवर्किंग ईव्हीएम की जानकारी देने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची को नियत समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करें। बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग शहडोल से वीडियो कांफ्रेंसिंग में शामिल हुए। इस दौरान उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री मनोज मालवीय, श्रीमती संजू कुमारी सहित अन्य अ?धिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली के रेस्टोरेंट में आग लगने से लोगों के निधन पर दुःख जताया

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह आग लगने से हुई दुर्घटना पर गहन दुःख जताया है। इस अग्निकांड में कई लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई और कुछ घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक हादसा है। उन्होंने बाबा महाकाल से दिवंगतों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।

श्रमोदय आदर्श आई.टी.आई. भोपाल में श्रमिकों के बच्चों के लिए निशुल्क आवासीय प्रवेश प्रक्रिया शुरू

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए भोपाल स्थित श्रमोदय आदर्श आई.टी.आई. में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत सरकार से एनसीवीटी मान्यता प्राप्त इस संस्थान में प्रवेश के इच्छुक आवेदक 26 मई से 30 जून 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके साथ ही 1 जून से 30 जून 2026 के मध्य चॉइस फिलिंग की सुविधा उपलब्ध रहेंगी। संस्थान में चयनित होने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान निशुल्क हॉस्टल और भोजन की सुविधा भी दी जाएगी।

इस प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 8वीं और 10वीं पास अभ्यर्थी संस्थान में संचालित आठ अलग-अलग ट्रेडों के लिए पात्र हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपने नजदीकी कियोस्क सेंटर के माध्यम से पंजीयन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं, तथा प्रवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर भी विजिट कर सकते हैं।

इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेड के लिए 20-20 सीटें निर्धारित हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन मेकाट्रोनिक्स, एडवांस सी.एन.सी. मशीनिंग टेक्नीशियन, सिविल इंजिनियर असिस्टेंट, आई.ओ.टी. (स्मार्ट सिटी), फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी और इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन प्रत्येक ट्रेड में 24-24 सीटें उपलब्ध हैं। संस्था के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने या ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर आवेदक हेल्पलाइन नंबर 9424454453 और 9826947798 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

रायसेन का बारना बांध खतरे में?

- **3 विधानसभाओं के 90 हजार हेक्टेयर खेतों को सींचने वाली लाइफ लाइन बदहाल, दिखने लगीं दरारें**

रायसेन (नप्र)। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक बेहद चिंताजनक जमीनी हकीकत सामने आई है। क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान माना जाने वाला बारना बांध आज खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। साल 1970 में

बना और 1975 से लगातार सिंचाई के काम आ रहा यह बांध भोजपुर, उदयपुरा और बुधनी विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसानों की आजीविका का मुख्य जरिया है। इस बांध के पानी से हर साल लगभग 90 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है, लेकिन आज इसकी जर्जर हालत को देखकर स्थानीय लोग और किसान सहमे हुए हैं।

दीवारों में दरारें और उखड़ा प्लास्टर बयां कर रहा हकीकत- बांध के ऊपर से गुजरने वाले किसी भी शख्स को इसकी बदहाली साफ नजर आ जाएगी। बांध की रेलिंगों का प्लास्टर जगह-जगह से उखड़ चुका है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि कई महत्वपूर्ण हिस्सों में गहरी दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग हर साल इसके रखरखाव और सुरक्षा के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपये के बजट का दावा करता है, लेकिन धरातल पर काम के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई है। आलम यह है कि बांध पर लगी स्ट्रीट लाइट के खंभे तो खड़े हैं, लेकिन उनमें बल्ब तक गायब हैं। रात के अंधेरे में यहां का खौफ और बढ़ जाता है।

स्थानीय किसान प्रतिनिधि, रायसेन ने कहा बारना बांध हमारे खेतों की जान है। इसकी दीवारों में दरारें आना सीधे तौर पर हमारी जिंदगी और फसलों को खतरे में डालना है। सरकार को तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए कि आखिर मेंटेनेंस का पैसा कहां खर्च हुआ।

भारी बारिश में बड़े हादसे की आशंका

ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि अगर समय रहते इस ऐतिहासिक बांध की सुध नहीं ली गई, तो आने वाले दिनों में यह किसी बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। मानसून की भारी बारिश के दौरान बांध में पानी का दबाव बढ़ने पर ये दरारें और चौड़ी हो सकती हैं, जिससे आसपास के दर्जनों गांवों की फसलें और इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि करोड़ों का मेंटेनेंस बजट डकारने वाले जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर लापरवाही पर कब जागेंगे?

मोदी सरकार ने एमपी को दी सौगात
जुलवानिया-खंडवा बैतूल होकर जाने NH 347 बी होगा अपग्रेड, 4415.50 करोड़ का आएगा खर्च

भोपाल (नप्र)। मोदी सरकार ने मध्यप्रदेश को नए नेशनल हाईवे को अपग्रेड करने की सौगात दी है। यह नेशनल हाईवे जुलवानिया-खंडवा बैतूल होकर जाएगा। इस हाईवे की एमपी में लंबाई 233.653 किमी है और इस पर 4415.50 करोड़ की लागत आएगी।

एमपी को नेशनल हाईवे के अपग्रेड करने की सौगात मिलने के बाद आदिवासी क्षेत्रों और नर्मदा नदी से सटे इलाकों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। साथ ही पर्यटकों को भी नर्मदा नदी के आसपास के इलाकों को समझने में आसानी होगी।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आदिवासी क्षेत्र खरगोन से खंडवा होते हुए निकलने वाले इस हाइवे के कारण यहां हर तरह के विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। यह नर्मदा जी का क्षेत्र है और पर्यटकों की दृष्टि बहुत ही अच्छा क्षेत्र है।

नए नेशनल हाईवे की खास बातें

* एनएच-347 बी हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी खंड पर मौजूदा इंटरमीडिएट लेन को पक्के शोल्डर स्टैंडर्ड के साथ 2 लेन की सड़क के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। यह 125.01 किमी लंबी होगी।

* एनएच 347 बी के देशगांव जुलवानिया खंड को हाइब्रिड एन्यूटी मोड के अंतर्गत 2 लेन से 4 लेन सड़क में विस्तारित किया जाएगा। यह 108.643 किमी होगा।

*233.653 किमी लंबी इस परियोजना पर 4415.50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

*परियोजना के अंतर्गत खरगोन जिले में 16.20 किमी लंबा ग्रीनफील्ड बायपास भी विकसित किया जाएगा।

* उन्नत कॉरिडोर एमपी में बेहतर कनेक्टिविटी बनाएगा और 6 पीएम गतिशक्ति आर्थिक नोड्स को जोड़ते हुए मल्टी मॉडल एकीकरण को बढ़ावा देगा।

इटारसी-बैतूल के बीच 22 किमी लंबा टाइगर कॉरिडोर मंजूर- केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के इटारसी-बैतूल इलाके में 22 किमी लंबे टाइगर कॉरिडोर को फोरलेन बनाने की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 758 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। कॉरिडोर बनने से माल ढुलाई में लगने वाले समय में कमी आएगी।

साकेत नगर में हिंदू लड़कियों के साथ होटल में पकड़ाया मुस्लिम युवक

जेब से निकले आपत्तिजनक सामान, लव जिहाद का आरोप

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मुस्लिम युवक को हिंदू संगठन के लोगों ने हिंदू लड़कियों के साथ पकड़ा है। एक हिंदू लड़की नाबालिग है। वहीं, युवक के जेब से आपत्तिजनक सामान मिला है। इसके आधार पर हिंदू संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि होटल में अनैतिक कार्य चल रहा था। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

एसएसजी होटल में पकड़े गए

दरअसल, भोपाल के बागसेवनिया थाना क्षेत्र के साकेत नगर एसएसजी होटल है। इसी होटल एक कमरे में मुस्लिम युवक दो हिंदू लड़कियों के साथ आया था। इसकी सूचना हिंदू संगठन के लोगों को मिल गई। वे लोग वहां पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी।

साथ में थीं दो लड़कियां

मुस्लिम युवक के साथ दो लड़कियां थीं। बताया जा रहा है कि उनमें एक लड़की नाबालिग है। हिंदू संगठन के लोगों के पहुंचते ही दोनों लड़कियां चेहरे ढक ली। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी युवक का वीडियो भी बनाया है।

जेब में आपत्तिजनक सामान- वहीं, मुस्लिम युवक के पास से आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। हिंदू संगठनों के लोगों का आरोप है कि वह लड़कियों को अनैतिक कार्य के लिए यहां लाया था। हालांकि विवाद के दौरान दोनों लड़कियां चुप रही हैं।

लव जिहाद का लगा रहे हैं आरोप- हिंदूवादी संगठन के लोग लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही थाने पहुंचकर नारेबाजी की है। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों युवतियों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

जांच कर रही है पुलिस

पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामला जांच के दायरे में है। नाबालिग होने के दावे की पुष्टि दस्तावेजों से की जा रही है। आपत्तिजनक सामग्री मिलने के आरोप की भी जांच होगी। फरार युवक की तलाश जारी है। सभी बिंदुओं पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया जा रहा है।

पटवारी ने धार्मिकयुक्त फोटो लगे दुपट्टे नीचे फेंके

बीजेपी हमलावर, प्रवक्ता बोले- पटवारी अमर्यादित और असभ्य आचरण के आदी सनातन और किसानों का अपमान किया

उज्जैन (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर आक्रामक टिप्पणी किए जाने के बाद सियासत गरमा गई थी। अब एक वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए जीतू पटवारी को घेरना शुरू कर दिया है।

मंगलवार को इंदौर से मंदसौर जाते समय जीतू पटवारी कुछ देर के लिए उन्हेल के पास किसान कांग्रेस के सम्मान कार्यक्रम में रुके थे। इसी दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक किसान पटवारी को श्री राधा-कृष्ण अंकित दुपट्टा भेंट करता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि पटवारी ने दुपट्टा हाथ में लेने के बाद पहले से गले में पहना हुआ एक अन्य धार्मिक दुपट्टा भी उतारा और दोनों दुपट्टों को नीचे लोगों के पैरों की ओर फेंक दिया।

सनातन धर्म और किसानों का अपमान बताया- वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी विवेक गुप्ता ने इसे सनातन धर्म और किसानों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी लगातार अमर्यादित व्यवहार करते रहे हैं। गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर टिप्पणी करने के बाद अब पटवारी ने किसानों और सनातन संस्कृति का भी अपमान किया है।

मुख्यसचिव जैन ने कलेक्टर्स के साथ अभियान संबंधी तैयारियों की समीक्षा की

जनकल्याण अभियान में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देना करें सुनिश्चित : मुख्य सचिव

भोपाल (नप्र)। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर्स से कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की प्राथमिकता के अनुरूप 5 जून से आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनकल्याण अभियान में पात्र हितग्राहियों को केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि इस दौरान विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम और स्वच्छता अभियान, जनकल्याण शिविर, प्राकृतिक खेती कार्य-शालाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गतिविधियों का उत्कृष्ट क्रियान्वयन हो जिससे देश में मध्यप्रदेश अग्रणी हो। मुख्य सचिव श्री जैन बुधवार को मंत्रालय से संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को वीडियो कांफ्रेंसिंग के साथ अभियान की तैयारियों की समीक्ष कर रहे थे।

मुख्य सचिव श्री जैन ने कलेक्टर्स से कहा है कि प्रदेश के लिए यह गौरान्वित करने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पूर्व खजुराहो से काउंट-डाउन शुरू हुआ है। ऐसे में हम सबका यह उत्तरदायित्व है कि शरीर को निरोगी रखने वाले योग

से जन-जन को जोड़ें और नया रिकार्ड कायम करें। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स प्रयास करें कि योग का एक कार्यक्रम जिले की ऐतिहासिक धरोहर अथवा पर्यटन स्थल पर जरूर आयोजित हो। बैठक में बताया गया कि गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड के लिए योग की व्यक्तिगत श्रेणी की गतिविधि 14 जून को भी होगी जिससे लोग टोल-फ्री नंबर 18003157008 पर पंजीयन करवा सकते हैं। इस दिन यह आयोजन सुबह 6.15 से 7.35 बजे तक होगा। मुख्य सचिव श्री जैन ने कलेक्टर्स से कहा कि प्रभारी मंत्री से समन्वय कर कलेक्टर्स विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक होने वाली सभी गतिविधियों के लिए प्लान तैयार करें। उन्होंने पिछले वर्ष एक पेड़ मां के नाम में मध्यप्रदेश की देश में टॉप रैंक होने पर बधाई देते हुए कहा कि इस वर्ष भी प्रदेश को अग्रणी रखने के लिए पूरी प्लानिंग से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पौध-रोपण किया जाए। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव 5 जून को भोपाल से अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पूरे प्रदेश में जल चेतना और पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पौध-रोपण जियो टैगिंग और क्यू आर कोड के साथ किया जाएगा। इस गतिविधि के तहत स्वच्छता अभियान चलाकर ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट की सफाई के साथ जल स्त्रोतों की सफाई और गहरीकरण के कार्य भी किए जाएंगे।

मुख्य सविच श्री जैन ने 12 से 18 जून की अवधि में हर ब्लाक में 3 दिवसीय जनकल्याण शिविर लगाने पर सर्वाधिक फोकस करने के कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हितग्राही का योजनाओं के लिए चयन और प्रचलित योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में पूरी गंभीरता बरतें। उन्होंने इस दौरान लोक सेवा गारंटी में प्राप्त शिकायतों के साथ ही समाधान एक दिन में प्राप्त आवेदनों का संतुष्टि पूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रयास हो कि समय-सीमा में ही आवेदकों की जायज मांगो और शिकायतों का समाधान हो जाए।

जनसमस्या निपटाने सीएस ने फिर दी कलेक्टरों को नसीहत

योजनाओं में पात्र हितग्राहियों का ही चयन हो; लोक सेवा गारंटी-समाधान एक दिन में क्लिक एक्शन लें

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एक बार फिर कलेक्टरों से कहा है कि वे लोगों की शिकायतों पर क्लिक एक्शन लें। खासतौर पर लोक सेवा गारंटी और समाधान एक दिन में आने वाले आवेदनों के निराकरण में टाइम लिमिट का ध्यान रखा जाए, ताकि लोगों को सुविधा मिलने में आसानी हो। जिलों में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने लगातार तीसरी बैठक में जन समस्याओं को लेकर कलेक्टरों को नसीहत दी है। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के लिए हितग्राही चयन करने में गड़बड़ी न हो और अपात्रों को लाभ न मिलने पाए।

मंत्रालय में पर्यावरण दिवस से योग दिवस तक चलने वाले कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर्स से कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की प्राथमिकता के अनुरूप 5 जून से आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनकल्याण अभियान में पात्र हितग्राहियों को केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि इस दौरान विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम और स्वच्छता अभियान, जनकल्याण शिविर, प्राकृतिक खेती कार्य-शालाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गतिविधियों का उत्कृष्ट क्रियान्वयन हो जिससे देश में मध्यप्रदेश अग्रणी हो।